



वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016



बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग



सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16



बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत



अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
अध्याय-I.	प्राक्कथन	3
अध्याय-II	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति - एक झलक	5
अध्याय-III	जन सेवा प्रदान - दक्षता और पारदर्शिता	11
अध्याय-IV	पेटेंट	18
अध्याय-V	डिजाइन	42
अध्याय-VI	व्यापार चिह्न	49
अध्याय-VII	भौगोलिक उपदर्शन	63
अध्याय-VIII	पेटेंट सूचना पद्धति एवं राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम)	70
अध्याय-IX	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	79
अध्याय-X	प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि-क्रियाकलाप	87
अध्याय-XI	मानव संसाधन	98



अध्याय - I

प्राक्कथन

बौद्धिक सम्पदा (आईपी) मानव कल्पना, सर्जनात्मकता व आविष्कारिता का उत्पाद है तथा इसमें आविष्कार, डिजाइन, ब्रांड व कलात्मक कार्य सम्मिलित हैं। बौद्धिक सम्पदा संरक्षण नवप्रयोग, ज्ञान आधारित उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। बौद्धिक सम्पदा के निर्माताओं को विधिक अधिकार के रूप में प्रदत्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रणाली नवप्रयोग, अनुसंधान व सर्जनात्मकता के उद्दीपन द्वारा समाज कल्याण को बढ़ावा देने में भी सहायक है। संतुलित बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रणाली देश के नव प्रयोग, शोध व विकास के उद्देश्यों का सहयोग करने वाले महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) का ढांचा विधिक, न्यायिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित है तथा यह पूर्णतया ट्रिप्स का अनुपालन करता है। सभी हितधारकों चाहे वे घरेलू हो अथवा विदेशी, को बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को महत्व देते हुए भारत में आईपी कानून आईपीआर में हो रहे वैश्विक विकास के साथ कदम से कदम मिला कर चलते हैं। भारत सरकार बौद्धिक सम्पदा के महत्व को अहमियत देती है तथा इसने नीति के साथ साथ विधिक परिवर्तन करके कई कदम उठाए हैं जो बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

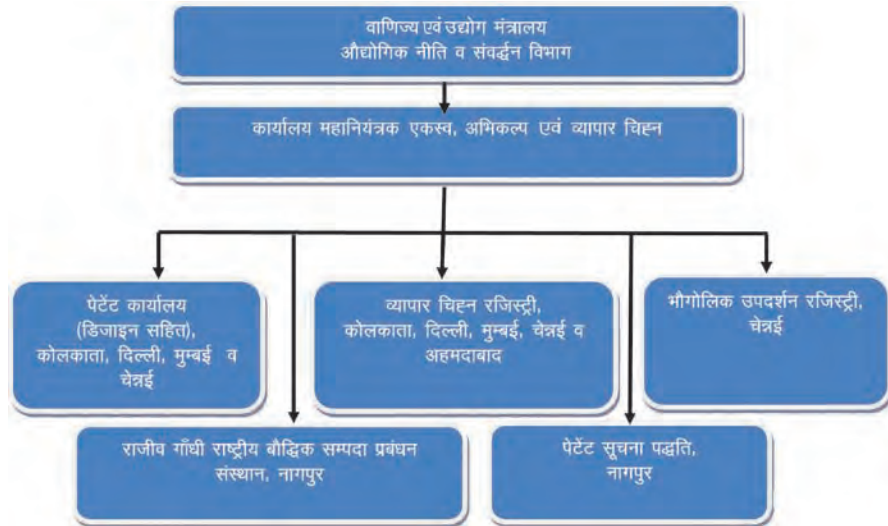
कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) का उद्देश्य सतत परिवर्तनशील बौद्धिक सम्पदा परिदृश्य की अपेक्षा पूरी करना है और यह अपने प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देने की आकांक्षा रखता है। इसका प्रयास रहा है कि देश के नवप्रयोग व विकास के उद्देश्यों को सहायता देने के लिए जीवंत व संतुलित बौद्धिक सम्पदा प्रणाली स्थापित हो। सभी हितधारकों को अभिगम सुलभ कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का संपूर्ण कायाकल्प हुआ है जिससे बौद्धिक सम्पदा आवेदनों की प्रक्रिया में अधिक दक्षता आई है, आवेदनों के परीक्षण में समरूपता और निरंतरता आई है, बौद्धिक सम्पदा संबंधित सूचना की पारदर्शिता और प्रसार बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग का विकास हुआ है तथा जन-सामान्य में बौद्धिक सम्पदा जागरूकता कर स्तर बढ़ा है।





कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) का अधीनस्थ कार्यालय है। यह कार्यालय पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न तथा भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित बौद्धिक सम्पदा विधानों का प्रशासन इस प्रकार से करता है जिससे देश में एक प्रभावी और जीवंत बौद्धिक सम्पदा प्रणाली सृजित की जा सके। नागपुर में स्थित पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) तथा राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) भी कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार एवं तथा भौगोलिक उपदर्शन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।

बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के संगठनात्मक चार्ट निम्नवत् हैं:



महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में दिया गया है। कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अंतर्गत सभी कार्यालयों के राजस्व एवं व्यय के ब्यौरे एवं अन्य संबद्ध सांख्यिकी भी शामिल की गई है। अद्यतन बौद्धिक सम्पदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यांश और अन्य उपयोगी सूचना हमारी शासकीय वेबसाइट (<http://www.ipindia.nic.in>) पर उपलब्ध है।

(ओम प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से.)

महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न



घ. भौगोलिक उपदर्शन : 15 सितम्बर, 2003 से 31 मार्च, 2016 तक कुल 543 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 17 आवेदन दाखिल किए गए और 200 आवेदनों का परीक्षण किया गया। कुल 26 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत् हैं।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
दाखिल	148	24	75	47	17
परीक्षित	37	30	42	60	200
पंजीकृत	23	21	22	20	26

ङ. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति: विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत् है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति - अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
पेटेंट	4,381 (8,488)	4,126 (9,027)	4,227 (11,411)	5,978 (14,316)	6,326 (20,429)
डिजाइन	6,590 (6,705)	7,252 (7,300)	7,178 (7,226)	7,147 (7,218)	7,904 (8,023)
व्यापार चिह्न	51,735 (57,867)	44,361 (69,736)	67,796 (1,04,756)	41,583 (83,652)	65,045 (1,16,167)
भौगोलिक उपदर्शन	23	21	22	20	26

शीर्ष 5 भारतीय पेटेंटग्राही

क्र.सं.	संगठन का नाम	अनुदानित पेटेंट
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	113
2	सैमसंग आर & डी इन्स्टिट्यूट इंडिया- बंगलोर प्राइवेट लिमिटेड	55
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	45
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	40
5	प्रतिरक्षा शोध एवं विकास संस्थान	32



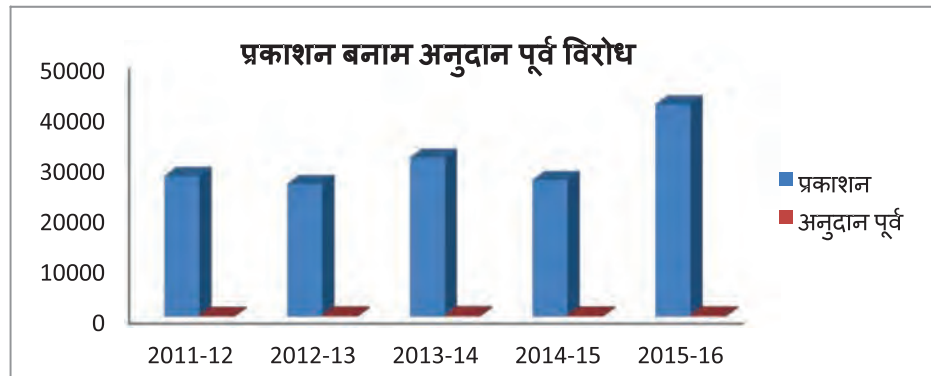


शीर्ष 5 विदेशी प्रवासी पेटेंटग्राही

क्र.सं.	आवेदक	अनुदानित पेटेंट
1	जीएम ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन्स, आईएनसी.	252
2	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	212
3	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईएनसी.	89
4	कोनिनक्लीके फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एन.भी.	68
5	होंडा मोटर क. लि.	65

च. प्रकाशन एवं अनुदान-पूर्व विरोध: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 11क के तहत **44,068** पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत सिर्फ **290** अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल हुए जो प्रकाशित आवेदनों का लगभग **0.70%** है। प्रकाशित तथा अनुदान-पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	प्रकाशन	अनुदान पूर्व विरोध
2009-10	34305	160
2010-11	32213	154
2011-12	27753	193
2012-13	26159	279
2013-14	31413	309
2014-15	26934	247
2015-16	41752	290





छ. राजस्व और व्यय: वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित कुल राजस्व ₹.587.44 करोड़ था जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 14% अधिक है, जबकि कुल व्यय ₹. 76.97 करोड़ था। पेटेंट व डिजाइन कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व ₹.403.98 करोड़ (पेटेंट ₹.398.40 करोड़ एवं डिजाइन ₹.5.58 करोड़) था, जबकि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने ₹.183.16 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने ₹.0.033 करोड़ तथा पेटेंट सूचना पद्धति और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान ने ₹.0.274 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रशासन से संबंधित राजस्व और व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है। आरेखीय प्रस्तुति केवल प्रतिवेदन वर्ष के आंकड़े दर्शाती है।

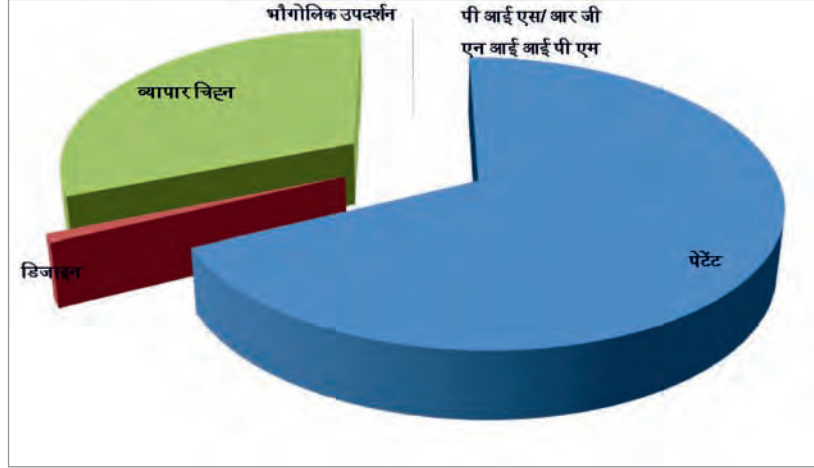
(i) वर्ष 2014 -2015 और 2015 -2016 के दौरान उत्पादित राजस्व का तुलनात्मक विवरण

	2014-2015 (लाख मे रु.)	2015-2016 (लाख मे रु.)
पेटेंट	37400.79	39840.40
डिजाइन	231.50	557.72
व्यापार चिह्न	13813.00	18316.01
भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री	5.56	3.32
पीआईएस/आरजीएनआई आईपीएम	12.80	27.42
कुल	51463.65	58744.89





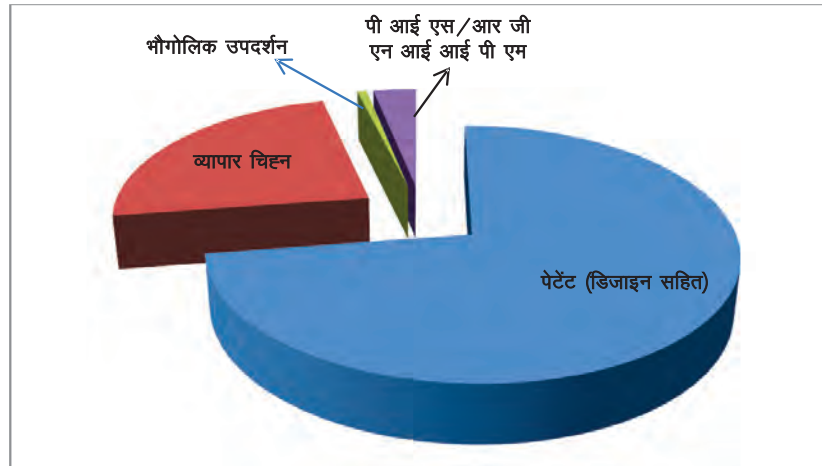
वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित राजस्व की आरेखीय प्रस्तुति



(ii) वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के व्यय की तुलना

वर्ष	2014-2015 (लाख में रु.)			2015-2016 (लाख में रु.)		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पेटेंट (डिजाइन सहित)	3318.10	2531.68	5849.78	3155.05	2435.62	5590.67
व्यापार चिह्न	555.20	1231.68	1786.88	706.50	1102.20	1808.70
भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री	-	69.63	69.63	-	54.14	54.14
पीआईएस/ आरजीएनआई आईपीएम	43.50	181.03	224.53	58.05	185.48	243.53
कुल	3916.80	4014.01	7930.81	3919.60	3777.44	7697.04

वर्ष 2015-16 के लिए आईपीओ में व्यय





अध्याय - III

जन सेवा प्रदान - दक्षता और पारदर्शिता

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) नवीन और उपयोगी वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी सूचना की बृहत्तम संभव उपलब्धता के माध्यम से समाज को संपन्न बनाता है और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को अत्यंत सुदृढ़ कर सकता है। यद्यपि, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि बौद्धिक सृजन से समाज के लाभान्वित नहीं होने की स्थिति में, अधिकार और आबन्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा जिस पर यह प्रणाली आधारित है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि सार्वजनिक सेवाओं को कुशलता से प्रदान करने व उत्पादकता तथा कार्य निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए सक्षम और पारदर्शी बौद्धिक सम्पदा प्रणाली विकसित हो।

पूर्व से विद्यमान सूचना प्रौद्योगिक सक्षम परिवेश को आगे बढ़ाते हुए, इस वर्ष के दौरान विद्यमान कंप्यूटर आधारित कार्य पद्धति का अद्यतीकरण करने और आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कई नई शुरुआत की गई है। इसके परिणामस्वरूप त्वरित और बेहतर सेवाएँ प्रदान करना संभव हुआ है। हमारी प्रणाली को अधिक डिजिटल सक्षम बनाना हमारा निरंतर प्रयास रहा है। ई-सेवाओं के फलस्वरूप आई दक्षता से न केवल कार्यालय के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है बल्कि हितधारकों के द्वारा आईपी सेवाओं की अभूतपूर्व मांग को पूरा करने में भी सहायता मिली है।

हाल के दिनों में, भारत ने बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट वैश्विक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उनमें से एक है, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर और आईपीईआर) तैयार करने और संचालित करने के लिए भारत के पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी (आईएसए) और अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी (आईपीईए) के रूप में कार्य करना। दूसरा है, भारत के मैट्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के बाद, उद्गम कार्यालय के रूप में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्य करना, जो उद्गम देश के अनुसार विभिन्न देशों में एक ही आवेदन दाखिल कर व्यापार चिह्न की वैधानिक संरक्षा प्राप्त करने का वायपो द्वारा प्रशासित व्यापार चिह्न के पंजीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है।





पेटेंट

पेटेंट आवेदन के लिए नई संख्या प्रणाली और परीक्षण हेतु अनुरोध: यह एक दीर्घकालिक आवश्यकता महसूस की गयी है कि पेटेंट कार्यालय में दाखिल पेटेंट आवेदन और परीक्षण हेतु अनुरोध की संख्या प्रणाली समान होनी चाहिए जैसी विश्व के अन्य महत्वपूर्ण आईपी कार्यालयों की है। पहले, पेटेंट कार्यालय की प्रत्येक शाखा (दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता) अपनी शाखा में प्राप्त क्रम संख्या के अनुसार आवेदन की संख्या देते थे। वर्ष के दौरान, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने 1 जनवरी, 2016 से पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन और परीक्षण हेतु अनुरोध के लिए नई विशिष्ट संख्या प्रणाली की शुरुआत की। कार्यालय ने चारों स्थान में एक विशिष्ट क्षेत्र के परीक्षण हेतु अनुरोधों को परीक्षण के लिए एक समान क्रमांक देने के लिए स्वतः आवंटन की प्रणाली की योजना की है जो अगले वर्ष के प्रारम्भ में शुरू की जाएगी।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा प्रणाली की ई-यात्रा का एक मुख्य आर्कषण खोज पोर्टल की शुरुआत थी जो पेटेंट के लिए लॉगइन मुक्त ऑन लाइन जन-खोज सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्ण पाठ शोध क्षमता वाली एक नवीन शोध सुविधा "इंडियन पेटेंट एडवांस्ड सर्च सिस्टम (इनपास)" की भी शुरुआत की गई। ऑन-लाइन खोज सुविधाओं को विस्तारित करते हुए 2015-16 में कार्यालय ने व्यापार चिह्न के पंजीकरण के उद्देश्य से माल और सेवाओं के वर्गीकरण हेतु ऑन-लाइन खोज सुविधा प्रदान की है और इस प्रकार कार्यालय व्यापार चिह्न के डाटा की सहज उपलब्धता के लिए हितधारकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

बहु आयामी सेवाएं: जनता के लाभ के लिए वेबसाइट पर बहुत सारी बहुआयामी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी हैं जिसमें जिस परीक्षण हेतु अनुरोध के लिए प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी की जा रही है वह माह प्रदर्शित करना; जिन परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) के लिए प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) आवेदक को जारी की गयी है उनकी समूह-वार व स्थान-वार जानकारी; निर्दिष्ट अवधि के दौरान संबंधित परीक्षण समूहों द्वारा पेटेंट आवेदनों के निपटान की स्थिति प्रदर्शित करना, पेटेंट कार्यालय की सभी स्थानों (अधिकार क्षेत्र व समूह-वार) द्वारा जारी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) का अवलोकन करना तथा आविष्कार के क्षेत्र के अनुसार पेटेंट आवेदन की गतिशील स्थिति का पता लगाने के लिए खोज प्रदान करना शामिल है। पेटेंट के लिए स्टॉक और फ्लो आधारित बहुआयामी सेवा उपलब्ध कराई गई है ताकि आवेदकों/हितधारकों के लिए वास्तविक समय आधार पर विभिन्न स्टॉक के अंतर्गत पेटेंट और विभिन्न चरणों में आवेदनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर नजर रखना संभव हो सके।



निम्नलिखित जानकारी उनकी संख्या, शीर्षक और तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्र के अनुसार एक आसानी से सुबोध प्रारूप में वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:

- पेटेंट जो समाप्त हो गए हैं, अर्थात 20 वर्ष की अवधि खत्म हो गयी है।
- नवीकरण शुल्क ने भरे जाने की वजह से जो पेटेंट प्रभावी नहीं रहे हैं।
- पेटेंट जो समाप्त हो गए हैं अथवा प्रभावी नहीं रहे हैं।

डिजाइन

नए आवेदन की ई-फाइलिंग की शुरुआत प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ होने से बिलकुल पहले की गई जिस पर निरंतर निगरानी रखते हुए प्रतिवेदन वर्ष के दौरान बेहतर जन सेवा प्रदान करने के लिए उसका अद्यतीकरण भी किया गया। परिणामस्वरूप ऑन लाइन माध्यम से दाखिल आवेदनों की संख्या में डिजाइन के लिए कुल आवेदनों में 20% तक की वृद्धि हुई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि डिजाइन (संशोधन) नियम 2014 के पिछले संशोधन में लघु इकाइयों के लिए 50% शुल्क छूट की सुविधा दी गई है। इसके फलस्वरूप डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% से अधिक की वृद्धि हुई है।

डिजाइन अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत गतिविधियों की विस्तृत जानकारी कार्यालय पद्धति व कार्य विधि के मैनुअल के साथ कार्यालय महानियंत्रक की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकरण और उत्तर पंजीकरण गतिविधियों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में नियमित रूप से खोज योग्य स्वरूप में पेटेंट कार्यालय जर्नल में प्रकाशित की जाती है। पंजीकृत डिजाइन के प्रकाशन में पंजीकृत डिजाइन की सर्वोत्तम छवि भी रहती है जिससे डिजाइन हितधारक पूर्व कला से परिचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजाइन स्कंध अनुरोध करने पर डिजाइन रजिस्टर की जाँच और पंजीकृत डिजाइन की पूर्व कला खोज भी उपलब्ध कराता है। डिजाइन आवेदन की स्थिति शासकीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। पंजीकृत डिजाइन की जन खोज सुविधा ऑन-लाइन उपलब्ध है।

आईएसओ प्रमाणन:

यह मानते हुए कि प्रमाणन विश्वसनीयता लाने के लिए जिससे यह पता चले कि कार्यालय द्वारा प्रदत्त उत्पाद या सेवाएँ उपभोक्ताओं की अपेक्षा पूर्ण करने के साथ साथ कार्यालय के लिए तय मानक को भी पूरा करने का एक उपयोगी साधन है, यह कार्यालय अपने विभिन्न स्कंधों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा है।





उल्लेखनीय है कि गुणता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) पेटेंट कार्यालय, कोलकाता के डिजाइन स्कंध में 2014 से लागू है। साथ ही साथ डिजाइन स्कंध ISO-9001:2008 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत है। डिजाइन स्कंध के सभी कर्मियों को इसकी जानकारी देने के लिए क्यूआईसी (क्वालिटी कांसिल ऑफ इंडिया) ने मैकलिड सर्टिफिकेशन्स के साथ मिलकर 22 से 23 जनवरी 2015 के दौरान ISO-9001:2008 पर एक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया। ISO-9001:2008 के संदर्भ में सभी दस्तावेज जैसे गुणता मैनुअल, एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) आदि तैयार किया गया है व गुणता नीति को भी अंतिम रूप दिया गया है। प्रमाणन निकाय बीएसआई (ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टिट्यूशन) द्वारा 26-3-2015 को स्टेज-1 ऑडिट किया गया। हालाँकि स्टेज-1 ऑडिट के दौरान कोई एनसी (नॉन कंफर्मिंटे) नहीं उठाया गया, लेखा परीक्षकों ने कुछ छोटी टिप्पणी अवश्य की जिसका अनुपालन स्टेज-2 ऑडिट के पहले किया जाना था। तत्पश्चात बीएसआई द्वारा 31-3-2015 को स्टेज-2 ऑडिट किया गया।

इन प्रयासों का पुरस्कार प्राप्त हुआ और डिजाइन स्कंध कोलकाता ने डिजाइन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत वस्तु के निर्माण एवं किसी पदार्थ संबंधी पंजीकरण के माध्यम से औद्योगिक डिजाइन की संरक्षा और रख रखाव के लिए बीएसआई भारत से 13-4-2015 को ISO-9001:2008 प्रमाण पत्र संख्या एफएम 634081 प्राप्त किया।

व्यापार चिह्न :

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की गतिविधियों को उसके विद्यमान अधिशासियों एवं कर्मचारियों की महत्तम उपयोग के लिए पुनर्गठित किया गया है। व्यापार चिह्न आवेदनों के साथ साथ पंजीकृत व्यापार चिह्न के विवरण आम जनता के लिए उपलब्ध है जिससे पारदर्शिता आती है।

व्यापार चिह्न आवेदनों का परीक्षण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, मुम्बई से केन्द्रीकृत रूप में जारी रहा। परीक्षण हेतु आवेदनों का आवंटन उनके दाखिल किए जाने की तिथि के क्रम में व्यापार चिह्न प्रणाली सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही किया जाता है व तदनुसार परीक्षण रिपोर्ट जारी की जाती हैं। इस प्रकार, व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण हेतु आवेदनों के आवंटन में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। पंजीकरण हेतु स्वीकृत आवेदनों का प्रकाशन व्यापार चिह्न जर्नल में साप्ताहिक आधार पर किया जाता है और उसे शासकीय वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, मुम्बई से केन्द्रीकृत रूप में व्यापार चिह्न





पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए जिसमें प्रमाण पत्रों का प्रकाशन व प्रेषण शामिल है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित और कार्यकारी की गई है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में पूर्ण पादर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबित व्यापार चिह्न आवेदनों एवं पंजीकृत व्यापार चिह्न, उनके साथ दाखिल सभी दस्तावेज की प्रति सहित, के विवरण शासकीय वेबसाइट www.ipindia.nic.in के माध्यम से वास्तविक समय आधार पर आम जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री जर्नल प्रत्येक सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय ने आवेदक या उसके प्राधिकृत एजेंट को ईमेल आईडी पर शासकीय पत्र भेजने की शुरुआत की है। अधिकांश बाहर भेजे जाने वाले शासकीय पत्रों की प्रतियाँ भी उनके आवेदनों के साथ शासकीय वेबसाइट पर दी गई हैं।

व्यापार चिह्न पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया स्वाचालित कर दी गई है। व्यापार चिह्न पंजीकरण के नवीकरण हेतु उपयुक्त आवेदन समय पर दाखिल करने पर, नवीकरण की प्रक्रिया और नवीकरण सूचना व्यापार चिह्न प्रणाली के माध्यम से अपने आप तैयार होती है और उसे उसके आवेदन (पंजीकृत व्यापार चिह्न) के विवरण के साथ शासकीय वेबसाइट पर रखा जाता है तथा आवेदक को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के भेजा जाता है।

व्यापार चिह्न की बहुआयामी सेवाएँ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह जनता को वास्तविक समय आधार पर व्यापार चिह्न आवेदनों के परीक्षण, कारण बताओ सुनवाई, व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशन, व्यापार चिह्न का पंजीकरण और परित्याग, अस्वीकृति आदि के माध्यम से आवेदनों के अन्य निष्पादन के विवरणों के साथ-साथ मासिक अथवा दिनांक अनुसार निर्गत अन्य सूचनाएं आम जनता के लिए उपलब्ध कराती है। टीएमआर में सुनवाई और स्थगन का विवरण वेबसाइट पर प्रदान किया जाता है।

व्यापार चिह्न के लिए **स्टॉक और फ्लो आधारित बहुआयामी** सेवा उपलब्ध कराई गई है ताकि आवेदकों/हितधारकों के लिए वास्तविक समय आधार पर विभिन्न स्टॉक के अंतर्गत व्यापार चिह्न और विभिन्न चरणों में आवेदनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पर नजर रखना संभव हो सके।





भौगोलिक उपदर्शन

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने 15 सितम्बर, 2003 से भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारंभ किया। 31 मार्च, 2016 तक रजिस्ट्री ने कुल 543 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त किए जिनमें से 261 पंजीकृत किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 30.9.2015 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने के लिए विशेष कदम उठाए गए जिसके परिणामस्वरूप 30.9.2015 तक प्राप्त सभी आवेदनों का प्रतिवेदन वर्ष के दौरान परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट जारी कर दी गयी। रजिस्ट्री ने 2009 से प्राधिकृत उपयोक्ता के पंजीकरण के लिए भी आवेदन प्राप्त करना शुरू किया और 2349 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए। कुल 1184 प्राधिकृत उपयोक्ता पंजीकृत हुए। आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की शुरुआत की गई है।

हितधारकों को विधायी हस्तांतरण में भागीदारी के लिए आमंत्रित करना:

यह कार्यालय सुदृढ़ परामर्श प्रक्रिया में विश्वास रखता है और जब कभी भी कार्यालय इसके विधान में कोई संशोधन प्रस्तावित करता है तो हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आमंत्रित की जाती है। वर्ष के दौरान प्रारूप पेटेंट व व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2016 तैयार किये गये जिसका उद्देश्य पेटेंट/व्यापार चिह्न प्रक्रिया में व्यवसाय करने की सरलता के तत्वों को शामिल करना और प्रक्रिया को प्रणालीगत करना था। उन्हें प्रकाशित किया गया और हिन्दी तथा अंग्रेजी में जनता के विचार आमंत्रित किए गए।

मध्यस्थता/समाधान प्रक्रिया:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने पहली बार दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, दिल्ली के विवादास्पद मामलों में मध्यस्थता की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य विरोधी मामलों में लम्बन कम करना था।

ऑन-लाइन सुविधा का विकास:

बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की बहुआयामी वेबसाइट है जिसमें पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन का आवेदन दाखिल करने और उस पर कार्यवाही करने संबंधी विवरण प्रदान किए जाते हैं। वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी एक लॉगइन-



मुक्त खोज पोर्टल में नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है ताकि सभी हितधारकों के बीच बौद्धिक सम्पदा सूचना का प्रसार सहज हो सके और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय की कार्य-पद्धति में उच्च स्तर की पारदर्शिता प्राप्त की जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्टार्ट अप इंडिया अभियान का अनुपूरण

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट अप इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस पहल का लक्ष्य स्टार्ट अप के विकास के लिए सहायक पारितंत्र बनाकर उद्यमशीलता और आविष्कारिता को बढ़ावा देना है।

इस शुरुआत के अनुपूरण में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसे इस उद्देश्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ने “स्टार्ट अप बौद्धिक सम्पदा संरक्षा (एसआईपीपी) सुविधा हेतु योजना” की शुरुआत बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षा प्रोत्साहित करने के लिए की जिसमें स्टार्ट अप को उनके पेटेंट, डिजाइन व व्यापार चिह्न आवेदन को दाखिल करने व आगे की प्रक्रिया हेतु सुविधा प्रदाता प्रदान करना व सुविधा प्रदाता के व्यावसायिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने स्टार्ट अप योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस योजना की झलक और उद्देश्य दर्शाने वाले दस्तावेज को तैयार किया गया व 18 जनवरी 2016 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने का इरादा रखने वाले आविष्कारकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाताओं की एक सूची भी तैयार की गयी व वेबसाइट पर अपलोड की गई। स्टार्ट अप के प्रश्नों का हल शीघ्रतिशीघ्र करने के लिए ई-मेल और सहायता डेस्क के माध्यम आवश्यक सहायता नियमित रूप से प्रदान की जाती है।

सूचना का अधिकार

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नीति उद्देश्यों के क्रियान्वयन के प्रति बौद्धिक सम्पदा कार्यालय पूर्णतया प्रतिबद्ध है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के सूचनार्थ शासकीय वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुसरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गई।





अध्याय - IV

पेटेंट

1. परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 44वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय भौगोलिक रूप से विभाजित है तथा चार महानगरों कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थित है। अब, सभी कार्यालय भौगोलिक सीमाओं के बिना सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए, एक आभासी कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। पेटेंट कार्यालय देश में हुए आविष्कारों पर इनके आवेदकों को सीमित एकाधिकार अनुदानित करने के द्वारा इन आविष्कारों की संरक्षा से संबंधित विधान का प्रशासन करता है। पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) पेटेंट अनुदान को प्रशासित करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप-रेखा प्रस्तुत करता है।

2. पेटेंट आवेदन:

वर्ष 2015-2016 में पेटेंट अनुदान के लिए दाखिल आवेदनों की संख्या **46,904** थी जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान यह संख्या 42,763 जो लगभग 10% की वृद्धि दर्शाती है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है सिवाय खाद्य, जैव तकनीकी, बायोमेडिकल, जैव रसायन, सामान्य अभियंत्रण और धातुकर्म क्षेत्रों के जिनमें विगत वर्ष की तुलना में आंशिक कमी देखी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े परिशिष्ट-ड और ड1 में दिखाए गए हैं।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

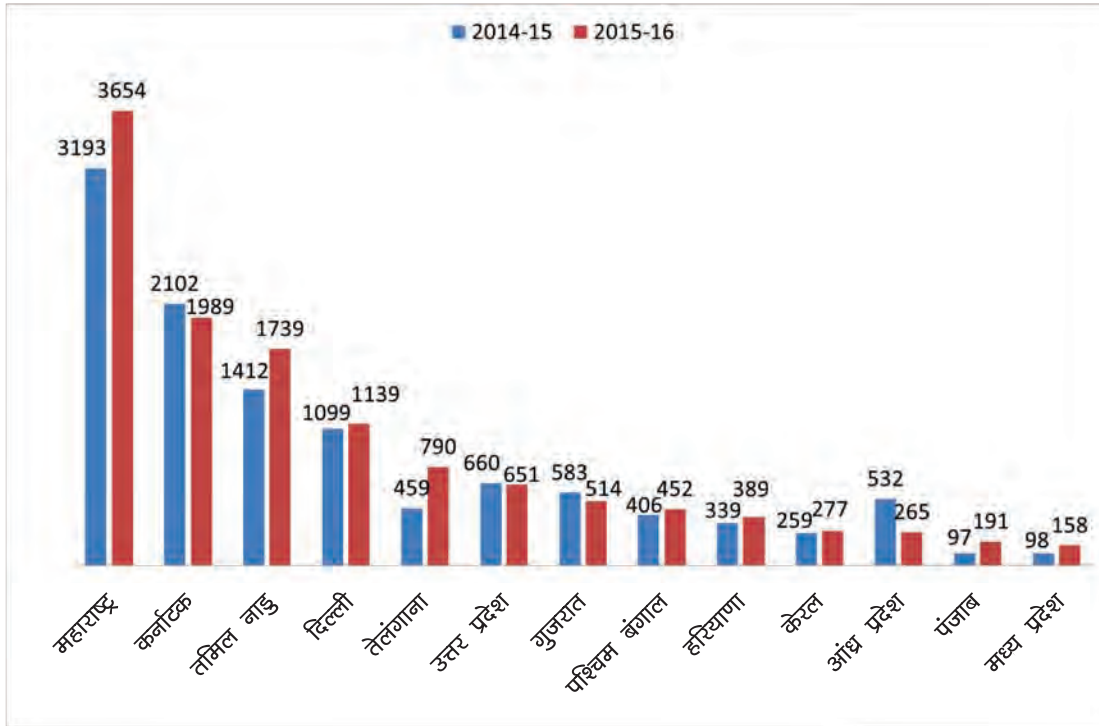
कुल **46,904** आवेदनों में से भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **13,066** रही जो विगत वर्ष से लगभग **8%** की वृद्धि दर्शाती है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या **12,071** थी। यही नहीं, वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या (**33,838**) में 2014-15 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या (**30,692**) की



तुलना में 10% की वृद्धि रही। भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल आवेदनों की कुल संख्या का लगभग 28% रही।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल सामान्य आवेदनों की कुल संख्या में वर्ष 2014-15 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या में अपने द्वारा दाखिल आवेदनों में 14% की वृद्धि के साथ इस वर्ष के दौरान भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। जहां तेलंगाना ने सूची में अपना प्रभावी स्थान बनाए रखा वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और पश्चिम बंगाल ने दाखिल आवेदनों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में मध्यम से उच्च वृद्धि दर्शायी है। ऐसे कुछ राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहां से पेटेंट दाखिल करने की संख्या कम है परन्तु वृद्धि की दर बहुत अधिक है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट ख में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदक द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों की तुलना (राज्यानुसार)





(ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष भारतीय आवेदक

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1.	सैमसंग आर & डी इन्स्टिट्यूट इंडिया	229
2.	टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड	213
3.	विप्रो लिमिटेड	149
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	60
5.	एचसीएल टेक्नोलॉजिस लि.	49

(ग) वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष भारतीय आवेदक

क्र.सं.	वैज्ञानिक तथा अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	323
2.	सैमसंग आर & डी इन्स्टिट्यूट इंडिया- बंगलोर प्राइवेट लिमिटेड	271
3.	महानिदेशक, प्रतिरक्षा अनुसंधान व विकास संगठन	85
4.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	63
5.	हेटेरो रिसर्च फाउंडेशन	40
6.	जी.एच.आर. लैब्स एंड रिसर्च सेंटर जी.एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग	33
7.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान	25
8.	संदीप इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर	21
9.	सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डेक)	20
10.	सन फार्मा एड्वान्स्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड	19



(घ) संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष भारतीय आवेदक

क्र.सं.	संस्थानों और विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	391
2.	अमिटी विश्वविद्यालय	99
3.	भरथ विश्वविद्यालय	65
4.	भारतीय विज्ञान संस्थान	46
4.	चितकार विश्वविद्यालय	46
5.	सविथा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सविथा विश्वविद्यालय	33
5.	जी.एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग/ जी.एच.आर. लैब्स एंड रिसर्च सेंटर	33
6.	शूलीनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज	22
6.	जर्नादन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (मानद) विश्वविद्यालय	22
7.	वेलटेक डॉ. आरआर एंड डॉ. एसआर टेक्निकल यूनिवर्सिटी	20
8.	सिद्धगंगा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टिट्यूट ऑफ श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसायटी	17
9.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फर्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर)	15
9.	डॉ. एम.जी.आर. एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट	15
10.	किंग जॉर्ज'स मेडिकल यूनिवर्सिटी	14





(ड) विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन

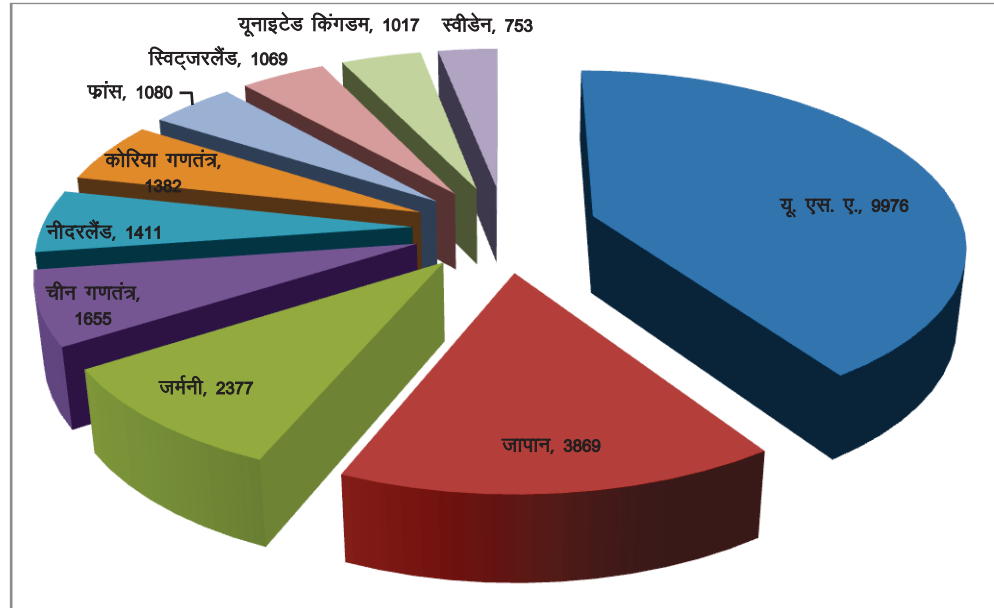
i. कन्वेंशन आवेदन:

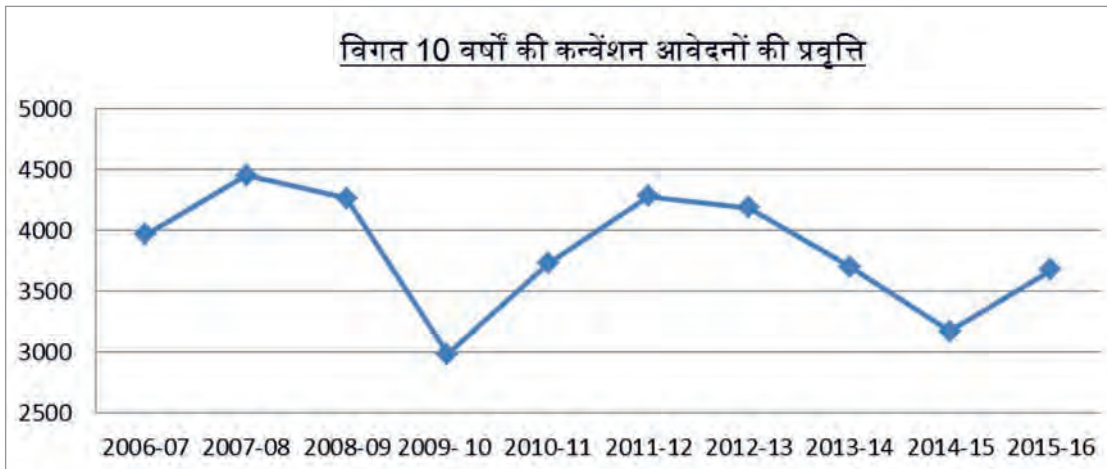
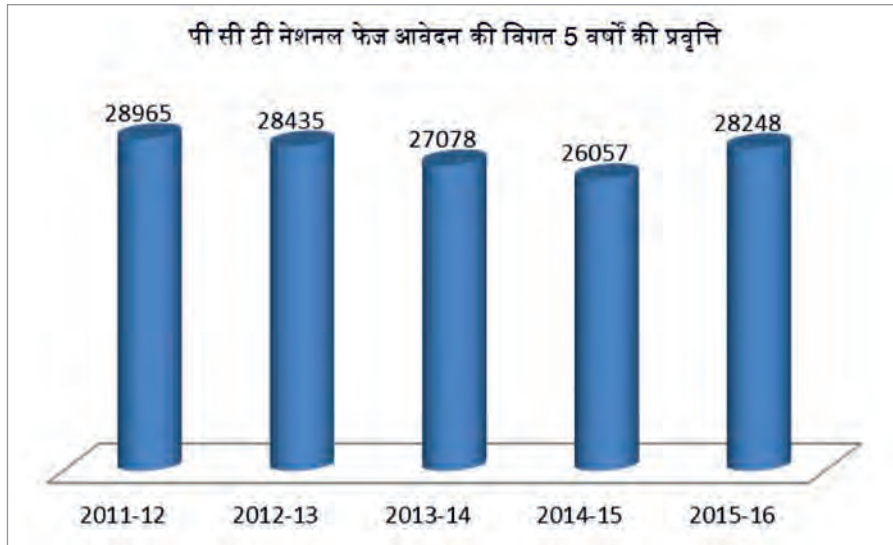
वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत प्रायिकता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या 3,675 थी। यह गत वर्ष दाखिल कन्वेंशन आवेदनों की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाता है।

ii. पी.सी.टी राष्ट्रीय फेज आवेदन:

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या 28,248 रही जो गत वर्ष की संख्या 26,057 की तुलना में 8% की वृद्धि दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष देश थे: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन गणतंत्र व नीदरलैंड। देशानुसार विवरण परिशिष्ट ख में प्रदर्शित किया गया है।

पी.सी.टी राष्ट्रीय फेज हेतु शीर्ष दस आवेदक (देशानुसार)





iii शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

निम्नलिखित तालिका उन शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2015-16 के दौरान पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं।





शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	1884
2.	कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी.	949
3.	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स क. लि.	905
4.	हुवाई टेक्नोलॉजी क. लि.	648
5.	जेनरल इलेक्ट्रीक कम्पनी	446
6.	टैलेफोनाक्विटबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	407
7.	माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एलएलसी	362
8.	टोयोटा जीडोसा काबुशीकी काइशा	304
9.	बेस्फ एसइ	302
10.	होंडा मोटर क. लि.	268

वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त एवं उद्गम देश तथा राज्य के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दर्शाया गया है।

2006-2007 से 2015-2016 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट "ग"** में दर्शायी गई है।

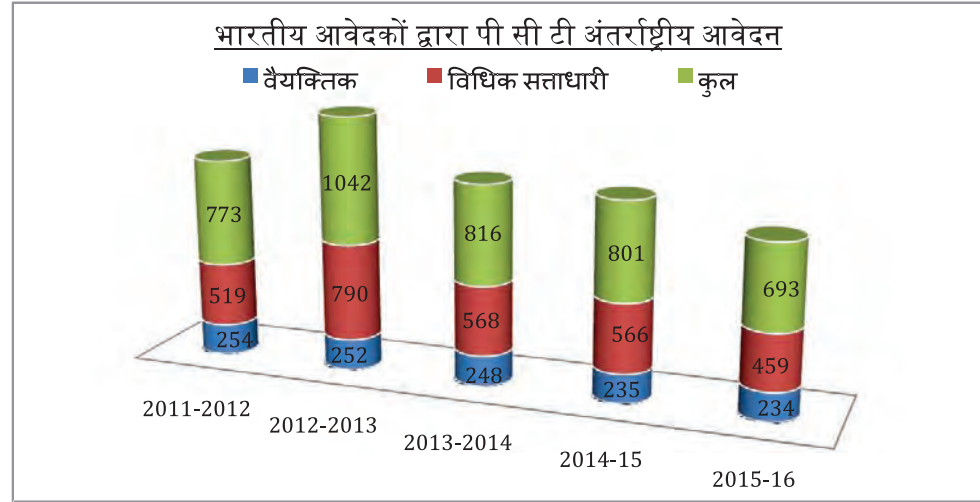
2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट "ड"** तथा **"ड1"** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित पेटेंट आवेदन

कार्यालय ने गत वर्ष के 22,631 आवेदनों की तुलना में वर्ष के दौरान 16,851 आवेदनों का परीक्षण किया। पेटेंट आवेदन जिनके लिए प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी उसमे कमी का कारण गत वर्ष की तुलना मे परीक्षण के लिए कम परीक्षकों की उपलब्धता रही।



आरओ/आईएन मे दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति



वर्ष के दौरान पी.सी.टी. अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों के सर्वप्रमुख अंशदाता थे- कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, लूपिन लिमिटेड, डॉ. रेड्डी लेबोरेट्री लिमिटेड, वॉकहार्ड लिमिटेड, ऑरिजिन डिस्कवरी टेक्नॉलोजी लिमिटेड और रैनबैक्सी लेबोरेट्री लिमिटेड आदि।

7. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँ

(क) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कार: वर्ष के दौरान पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत 135 आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से 20 आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, 70 आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत हुए तथा वर्ष के अंत तक 45 आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) धारा 11क के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशन: वर्ष के दौरान धारा 11क के तहत 44,068 आवेदन प्रकाशित किए गए जिनमें वैसे 2,316 आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत है:



वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
धारा 11क के तहत प्रकाशन	26,422	24,746	29,744	25,358	41,752
शीघ्र प्रकाशन	1,331	1,413	1,669	1,576	2,316
कुल	27,753	26,159	31,413	26,934	44,068

(ग) अनुदानपूर्व आपत्ति [धारा 25(1) के तहत]: अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में, कार्यालय में 290 आवेदन प्राप्त हुए व 88 अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(घ) अनुदानोत्तर आपत्ति [धारा 25(2) के तहत]: वर्ष के दौरान, 06 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। 10 अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया और प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक 160 अनुदानोत्तर आपत्तियाँ निष्पादन हेतु लंबित रही।

(ङ) गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत): वर्ष के दौरान, 95 पेटेंट आवेदन भारत सरकार, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के प्रतिरक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान 82 आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। वर्ष 2015-16 के अंत तक 13 आवेदन डीआरडीओ में लंबित रहे।

(च) देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत): भारत से बाहर आवेदन दाखिल करने की अनुमति का अनुरोध करते हुए 4,271 आवेदन फॉर्म 25 पर प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान ऐसे 4,152 आवेदनों पर अनुमति प्रदान कर दी गई।

(छ) व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत): 2015-16 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए 81 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान 68 आवेदन प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत): इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए 934 मामले प्राप्त किए गए व प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 477 आवेदनों का निपटान कर दिया गया।





(झ) जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत): वर्ष के दौरान, पेटेंट कार्यालय ने फॉर्म-27 पर जारी पेटेंट के 39,507 कथन प्राप्त किए। 8,589 पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्रवृत्त पेटेंट	39,989	43,920	42,632	43,256	44,524
प्राप्त फॉर्म-27	27,825	27,946	33,088	31,990	39,507
जारी रहने के रूप में दर्शाया हुआ	7,431	6,201	8,435	7,900	8,589

(ञ) अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92-क के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसको नियंत्रक द्वारा तार्किक आदेश के माध्यम से अस्वीकृत ठहरा कर निपटारा किया गया।

(ट) सूचना (धारा 153 के तहत): वर्ष के दौरान पेटेंट नियम, 2003 के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति करने के लिए पेटेंट कार्यालय ने 119 अनुरोध प्राप्त किए।

(ठ) अनुलिपि पेटेंट प्रमाण पत्र (धारा 154 के तहत): कुल 15 अनुरोध प्राप्त किए गए तथा 14 का निपटारा वर्ष के दौरान किया गया।

(ड) पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण: वर्ष के दौरान 10 नए पेटेंट अभिकर्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2016 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ताओं की कुल संख्या 2,424 थी।

8. राजस्व एवं व्यय:

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम एवं नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों से शुल्क के रूप में लगभग ₹. 398 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वर्ष के दौरान व्यय (डिजाइन प्रशासन सहित) ₹. 55.91 करोड़ था। पेटेंट मद में शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व का विवरण परिशिष्ट-छ में दिया गया है।





9. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए 317 अनुरोध प्राप्त किए गए और अधिनियम के तहत प्रदत्त समय-सीमा के अनुसार सभी अनुरोधों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई।

10. भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी व अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में कार्य करना

15 अक्टूबर 2013 से भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी (आईपीईए) के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया है। आईपीओ के आईएसए/आईपीईए के रूप में कार्य करने से संबन्धित पेटेंट (संशोधन) नियम, 15 अक्टूबर, 2013 से प्रभावी हुए।

31.3.2016 तक अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करने के लिए आईपीओ ने कुल 1365 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त किए। 31.3.2016 तक **1141 अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट** जारी की गई। कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकारी (आईपीईए) के रूप में **35 अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों** के संदर्भ में प्रारम्भिक परीक्षण की मांग प्राप्त की है जो परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा आईएसए के रूप में आईएसआर हेतु प्राप्त पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों का विवरण

आईएसए आवेदनों की गतिविधि	2013-14	2014-15	2015-16
दाखिल	135	519	711
वर्ष के आरंभ में लंबित	0	116	129
निपटाए गए	18	502	621
आहरित	1	4	1
लंबित	116	129	218



11. सामान्य सूचना

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी-रोम्स, पुस्तकें और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई-जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश में पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से अन्वेषण संचालित करने हेतु हजारों लोगों ने पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों का दौरा किया।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्रदत्त निःशुल्क ऑनलाइन इंटरनेट अन्वेषण सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

परिशिष्ट "क"

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
01	बायोकेमेस्ट्री जैव रसायन	5
02	बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी	7
03	बायोमेडिकल अभियंत्रण	8
04	रसायन	28
05	सिविल अभियंत्रण	1
06	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रण	17
07	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स	32
08	यांत्रिकी	16
09	धातुकर्म	7
10	भौतिकी	2
11	पॉलीमर	4
12	वस्त्र	5
	कुल	132



परिशिष्ट "ख"

वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन
उद्गम राज्य/राष्ट्र के अनुसार वर्गीकृत

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
अंडमान & निकोबार	1	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	265	532	0	1	10	30
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0
असम	55	46	0	0	3	5
बिहार	25	31	0	0	3	4
चंडीगढ़	41	24	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	22	28	0	0	0	0
दादर & नागर हवेली	0	2	0	0	0	0
दमन & दीव	1	0	0	0	0	1
दिल्ली	1139	1099	0	3	15	29
गोवा	32	16	0	0	0	1
गुजरात	514	583	0	0	15	2
हरियाणा	389	339	2	1	4	3
हिमाचल प्रदेश	55	16	0	0	0	2
जम्मू & कश्मीर	23	17	0	0	0	0
झारखंड	126	109	0	0	1	0
कर्नाटक	1989	2102	13	18	18	14
केरल	277	259	3	0	0	4
मध्य प्रदेश	158	98	1	2	0	1
महाराष्ट्र	3654	3193	8	10	37	64
मणिपुर	0	5	0	0	0	0
मेघालय	1	0	0	0	0	0
मिजोरम	9	0	0	0	1	0
नागालैंड	1	0	0	0	0	0





वार्षिक प्रतिवेदन 2015-2016

उड़ीसा	73	88	0	0	2	0
पाण्डिचेरी	12	16	0	0	0	0
पंजाब	191	97	0	0	1	0
राजस्थान	150	147	0	0	0	2
सिक्किम	9	1	0	0	0	0
तमिलनाडु	1739	1412	8	4	9	7
तेलंगाना	790	459	0	1	5	2
त्रिपुरा	12	8	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	651	660	1	1	3	4
उत्तरांचल	45	61	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	452	406	2	0	0	0
कुल योग	12901	11855	38	41	127	175

परिशिष्ट-“ख” जारी

राष्ट्रमंडल देश

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
यू.के.	57	18	91	68	1017	973
आस्ट्रेलिया	5	8	14	9	249	261
कनाडा	12	7	9	23	333	285
श्रीलंका	0	0	0	0	3	3
आयरलैंड	46	39	21	8	77	87
न्यूजीलैंड	0	1	0	2	40	56
कुल	120	73	135	110	1719	1665



उत्तर व दक्षिण अमरीका

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
यू.एस.ए	951	760	888	705	9976	8237
मैक्सिको	0	0	0	1	23	28
ब्राजील	0	6	2	6	44	48
बरमूडा	0	0	0	0	8	14
केमेन आइलैंड	0	0	0	0	40	22
वर्जिन आइलैंड	0	0	0	0	24	44
क्यूबा	0	0	0	0	4	7
कोलंबिया	0	0	0	0	3	5
अर्जेन्टीना	0	1	4	1	3	8
चिली	0	0	1	2	8	14
बहमास	0	0	0	1	4	1
बारबाडोस	0	0	0	0	6	2
वेनेजुएला	0	0	1	0	1	2
पेरू	0	0	0	0	5	0
पराग्वे	0	0	0	0	9	1
जमैका	0	0	0	1	1	0
ब्रिटिश वर्जिनिया	0	0	3	0	0	2
बेलाइज	0	0	0	0	1	1
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	0	0	0	0	7	2
कुल	951	767	899	718	10167	8438





यूरोप

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
इटली	8	5	53	49	551	529
जर्मनी	168	96	420	412	2377	2581
बेल्जियम	10	4	10	7	247	265
फ्रांस	71	85	112	148	1080	1236
स्पेन	42	2	17	11	141	171
स्विट्जरलैंड	104	144	212	153	1069	1252
फिनलैंड	28	23	29	30	188	229
आस्ट्रिया	2	0	37	16	269	209
नीदरलैंड्स	60	38	27	18	1411	1267
स्वीडन	21	25	36	44	753	835
डेनमार्क	24	18	16	6	272	341
पुर्तगाल	0	0	0	0	17	11
हंगरी	0	0	0	0	16	21
लग्जमबर्ग	0	0	7	5	68	69
रूस	5	1	1	1	87	88
रोमानिया	0	0	0	0	2	3
टर्की	0	0	1	4	22	22
स्लोवेनिया	0	0	0	0	19	11
नार्वे	5	0	0	0	90	86
साइप्रस	0	1	0	0	11	8
पोलैंड	0	0	9	8	27	38
बुल्गारिया	0	0	1	1	3	6
आइसलैंड	7	0	0	0	1	1
चेक गणराज्य	0	1	2	7	27	12
लिथेन्सटिन	0	0	0	0	25	12
यूक्रेन	0	0	0	0	9	5
स्लोवाकिया	0	0	0	0	6	3
ग्रीस	0	0	1	1	22	13
माल्टा	0	0	0	0	14	26
इस्टोनिया	0	0	1	0	2	2
लात्विया	0	0	0	0	5	1
क्रोएशिया	0	0	0	0	2	1
अन्य यूरोपियन देश	1	2	0	0	11	10
कुल	551	445	992	921	8844	9365





परिशिष्ट- "ख" जारी

अफ्रीका

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
दक्षिण अफ्रीका	3	1	1	2	47	65
मॉरिसस	2	9	0	0	1	1
सेशेल्स	0	0	0	0	1	2
स्वाजीलैंड	0	1	3	5	1	1
केन्या	0	0	0	0	5	2
इजिप्ट	1	0	0	0	6	2
ट्यूनिशिया	0	0	0	0	1	1
अन्य अफ्रीकी देश	0	0	0	0	4	0
कुल	6	11	4	7	66	74





एशिया

देश	साधारण		कन्वेंशन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
जापान	76	43	890	994	3869	4388
कोरिया गणराज्य	114	52	278	179	1382	726
चीन	8	5	145	87	1655	874
इजराइल	3	1	28	14	290	293
ताइवान	53	33	267	119	20	24
इंडोनेशिया	0	0	3	1	3	0
वियतनाम	0	0	0	0	3	3
सिंगापुर	22	18	4	12	92	98
मलेशिया	1	2	12	4	16	39
यू.ए.ई	5	6	0	1	17	3
फिलीपिंस	0	0	2	1	5	8
थाइलैंड	1	2	4	3	10	12
हाँग-काँग(चीन)	0	0	8	3	12	6
सउदी अरब	1	2	0	0	64	29
ईरान	0	0	0	0	1	2
बंगलादेश	0	0	0	0	2	3
कतर	0	0	0	0	3	5
अन्य एशियाई देश	3	0	1	0	6	2
कुल	287	165	1642	1418	7450	6515
कुल योग	14816	13316	3713	3215	28375	26232

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वालों द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
भारत में रहने वाले प्रवासी	5314	6040	6161	7044	8312	8921	9911	10941	12071	13066
साधारण	693	834	681	826	816	1031	1144	1228	1461	1915
कन्वेंशन	3969	4453	4264	2986	3728	4280	4184	3704	3174	3675
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	19768	23891	25706	23431	26544	28965	28435	27078	26057	28248
कुल योग	28940	35218	36812	34287	39400	43197	43674	42951	42763	46904





परिशिष्ट- "घ"

वर्ष 2006-2007 से 2015-2016 की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण के लिए अनुरोधों की संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल नहीं करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1)	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-07	28940	20645	694	1121	1907	5632	3473	13593
2007-08	35218	22146	1066	479	3173	12088	7966	21722
2008-09	36812	30595	888	1075	2541	13520	6158	24664
2009-10	34287	28653	2720	5171	1725	4443	6781	30553
2010-11	39400	31493	185	5186	1273	6236	7301	32293
2011-12	43197	33811	698	3800	699	3682	7545	32444
2012-13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013-14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014-15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015-16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218



परिशिष्ट- "ड"

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2011-2012 से 2015-2016 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

वर्ष	रसायन	औषधि	कंप्यूटर/इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	बायो-मेडिकल	यांत्रिकी	पोलिमर विज्ञान/तकनीक	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट ड 1 देखें)	कुल
2011-2012	6698	2762	4225	4390	4160	2586	1066	9716	1209	6385	43197
2012-2013	6812	2954	4424	4163	3568	2593	1053	10198	1425	6484	43674
2013-2014	6769	2507	4410	4039	4371	2230	612	11318	1050	5645	42951
2014-2015	6454	2640	4285	4380	4031	2529	1669	10031	1059	5685	42763
2015-2016	6463	2966	5988	5770	4102	2852	1579	10164	1230	5790	46904

परिशिष्ट-ड 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2015-16 के दौरान दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/ वर्ष	जैव तकनीकी	सामान्य अभियांत्रिकी	सिविल	वस्त्र	धातुकर्म/सामग्री विज्ञान	एग्रोकेमिकल	खाद्य	जैवरसायन	माइक्रोवायोलाॅजी	कृषि अभियंत्रण	पारंपरिक ज्ञान
2011-2012	788	822	373	536	598	484	294	179	629	139	1543
2012-2013	832	1561	658	556	594	486	452	366	547	190	242
2013-2014	647	652	798	634	582	422	387	190	495	234	604
2014-2015	1035	775	704	629	740	418	395	384	308	229	68
2015-2016	887	757	749	734	727	479	387	372	316	268	114





परिशिष्ट-“च”

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-2016 तक
अनुदानित पेटेंट की संख्या

वर्ष	रसायन	औषधि	कंप्यूटर/ इलेक्ट्रॉनि क्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	यांत्रि की	पोलिमर विज्ञान/ तकनी क	अन्य क्षेत्र (परिशि ष्ट ड 1 देखें)	कुल
2011-2012	1168	282	584	318	228	95	888	134	684	4381
2012-2013	1289	344	510	273	188	65	749	169	539	4126
2013-2014	1111	256	690	375	237	109	645	165	638	4226
2014-2015	1533	389	835	538	376	142	1047	295	823	5978
2015-2016	1683	370	810	414	362	175	1414	279	819	6326

परिशिष्ट -च1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 के दौरान
अनुदानित पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र/ वर्ष	जैव तकनी की	सामा न्य अभि यांत्रि की	वस्त्र	धातुकर्म/ सामग्री विज्ञान	बायो - मेडि कल	सिविल	जैव रसा यन	एगो केमि कल	माइ क्रो वायो लॉजी	खाद्य	कृषि अभि यंत्रणा
2011- 2012	309	153	60	40	24	37	38	-	-	21	2
2012- 2013	144	121	61	53	11	34	17	30	27	37	4
2013- 2014	220	112	52	36	12	32	56	44	21	51	2
2014- 2015	262	145	74	53	70	38	66	24	41	48	2
2015- 2016	185	142	94	94	69	60	52	45	44	32	2



अध्याय - V

डिजाइन

1 परिचय:

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षा डिजाइन अधिनियम, 2000 और तत्संबंधी डिजाइन नियम, 2001 द्वारा प्रशासित होता है जो दिनांक 11 मई, 2001 को अपने पूर्ववर्ती 1911 के अधिनियम को निरस्त कर प्रभावी हुआ। डिजाइन नियम, 2001 को डिजाइन (संशोधन) नियम, 2008 और इसके बाद डिजाइन (संशोधन) नियम 2014 द्वारा संशोधित किया गया जो 30 दिसम्बर, 2014 को प्रभावी हुआ व जिसमें नैसर्गिक व्यक्ति के साथ-साथ लघु इकाई और लघु इकाई के अलावा अन्य आवेदक के रूप में एक नई श्रेणी शामिल की गई है।

औद्योगिक डिजाइन पृष्ठ के ढंग तथा साज-सज्जा तथा पंक्तियों एवं रंग के संयोजन के साथ-साथ नये आकार व संरचनाओं के वैशिष्ट्य का सृजन तथा दृष्टिगत अनुरोध के संवर्द्धन हेतु वस्तुओं में प्रयुक्त अलंकरण को प्रमाणित करता है।

डिजाइन पंजीकरण के आवेदनों को डिजाइन नियम, 2001 की तृतीय अनुसूची के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है। यह मुख्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है जिसे लोकार्नो वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है।

औद्योगिक डिजाइन के पंजीकरण और संरक्षा संबंधी गतिविधियों का संचालन पेटेंट कार्यालय, कोलकाता के डिजाइन स्कंध द्वारा किया जाता है। हालाँकि डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन सभी चार कार्यालयों में दाखिल किए जा सकते हैं। नए आवेदन की ई-फाइलिंग की शुरुआत प्रतिवेदन वर्ष के प्रारंभ के समय ही की गई जिस पर निरंतर निगरानी रखते हुए प्रतिवेदन वर्ष के दौरान बेहतर जन सेवा प्रदान करने के लिए उसका अद्यतीकरण भी किया गया। परिणामस्वरूप ऑन लाइन माध्यम से दाखिल आवेदनों की संख्या में डिजाइन के लिए कुल आवेदन में 20% तक की वृद्धि हुई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि डिजाइन (संशोधन) नियम 2014, के पिछले संशोधन में लघु इकाइयों के लिए 50% शुल्क छूट की सुविधा दी गई है। इसके फलस्वरूप डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में 19% से अधिक की वृद्धि हुई है।



डिजाइन अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत गतिविधियों की विस्तृत जानकारी कार्यालय पद्धति के मैन्युअल के साथ कार्यालय महानियंत्रक की शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। डिजाइन अधिनियम, 2000 के तहत पंजीकरण और उत्तर पंजीकरण गतिविधियों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में नियमित रूप से खोज योग्य स्वरूप में पेटेंट कार्यालय जर्नल में प्रकाशित की जाती है। पंजीकृत डिजाइन के प्रकाशन में पंजीकृत डिजाइन की सर्वोत्तम छवि भी रहती है जिससे डिजाइन हितधारक पूर्व कला से परिचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजाइन स्कंध अनुरोध करने पर डिजाइन रजिस्टर की जाँच और पंजीकृत डिजाइन की पूर्व कला खोज भी उपलब्ध कराता है। आवेदन की स्थिति शासकीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। पंजीकृत डिजाइन की जन खोज सुविधा ऑन-लाइन उपलब्ध है।

डिजाइन पंजीकरण कार्य के संदर्भ में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) स्थापित करने के लिए कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने डिजाइन आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ISO 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त किया है। यह प्रमाणन बीएसआई (ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीच्यूशन) द्वारा दिनांक 13/04/2015 को प्रदान किया गया। वर्तमान में यह प्रमाण पत्र वार्षिक कंटेन्यूअस असेसमेंट विजिट (सीएवी) के अध्यक्षीन मार्च 2018 तक वैद्य है। ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र डिजाइन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत किसी वस्तु के निर्माण और किसी पदार्थ संबंधी पंजीकरण के माध्यम से औद्योगिक डिजाइन की संरक्षा और रख रखाव के लिए दिया गया है।

सीजीपीडीटीएम/डीआईपीपी और ओएचआईएम (अब ईयूआईपीओ) के बीच द्विपक्षीय सहयोग आईपीसी-ईयूआई (ईयू-भारत बौद्धिक सम्पदा समन्वय) के नाम से वर्तमान में जारी है। डिजाइन के संदर्भ में इस परियोजना के मुख्य घटक हैं:-

- क) डिजाइन आवेदनों की प्रक्रिया में गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में सर्वोत्तम व्यवहार का आदान-प्रदान
- ख) डिजाइन परीक्षण में सर्वोत्तम व्यवहार का आदान-प्रदान।



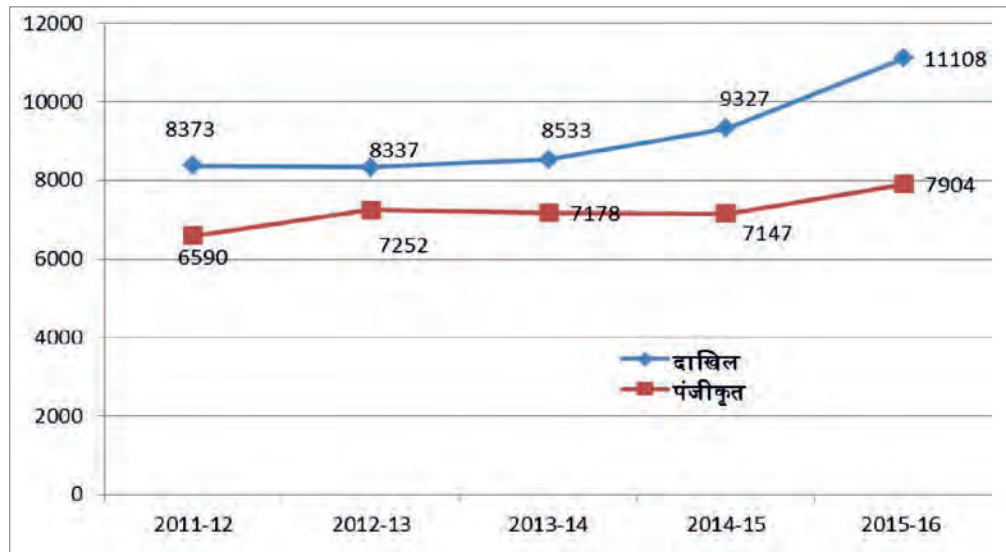


इस परियोजना के तहत ओएचआईएम के गुणता प्रबंधन दल के अधिशासियों ने डिजाइन स्कंध कोलकाता का 10 से 12 अगस्त, 2015 के दौरान दौरा किया और परीक्षकों एवं नियंत्रकों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा की। तत्पश्चात जनवरी, 2016 के दौरान डिजाइन स्कंध के अधिशासियों ने भी उक्त कार्यक्रम के अंश के रूप में ओएचआईएम का दौरा किया।

2. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों की संख्या 11,108 थी और पंजीकृत आवेदनों की संख्या 7,904 थी।

डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

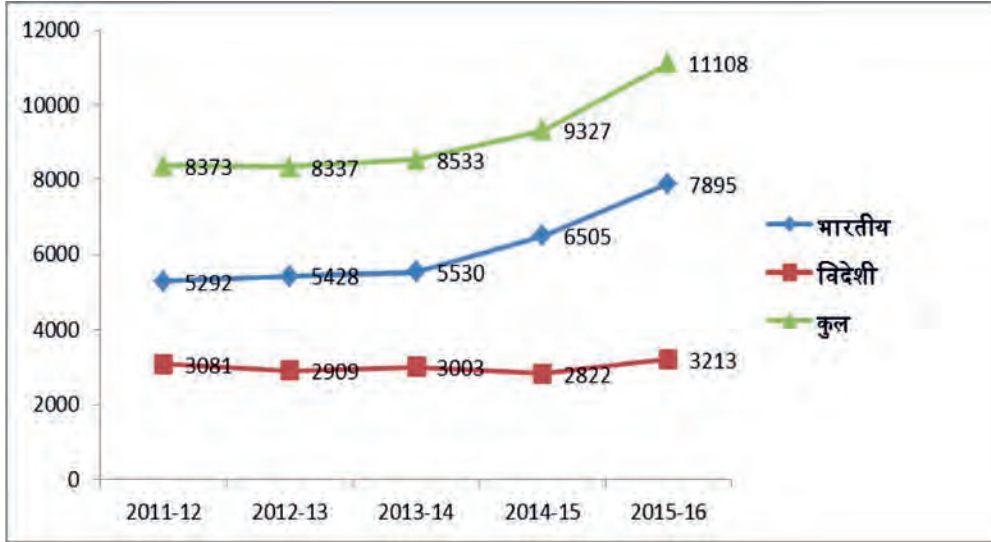


भारतीय एवं विदेशी नागरिकों द्वारा दाखिल आवेदन:

भारत में उद्गमित आवेदनों की संख्या 7895 थी जबकि 3213 आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। भारत से उद्गमित आवेदनों की संख्या कुल आवेदन का 71 प्रतिशत थी जो कि विगत वर्ष से लगभग 1400 आवेदन अधिक है।

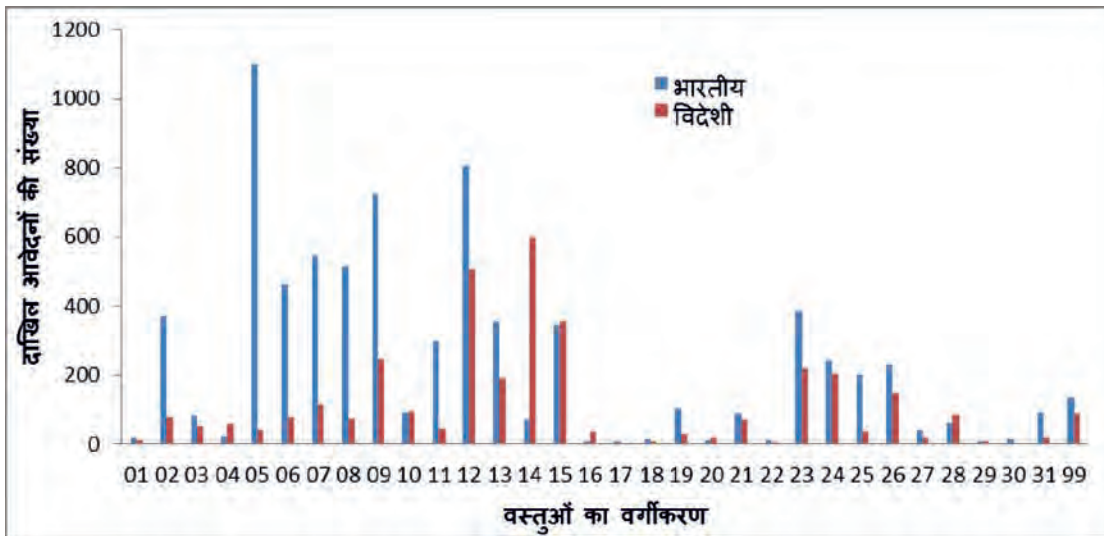


भारतीय और विदेशी उद्गम की आवेदन प्रवृत्ति निम्नवत है :



वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदन

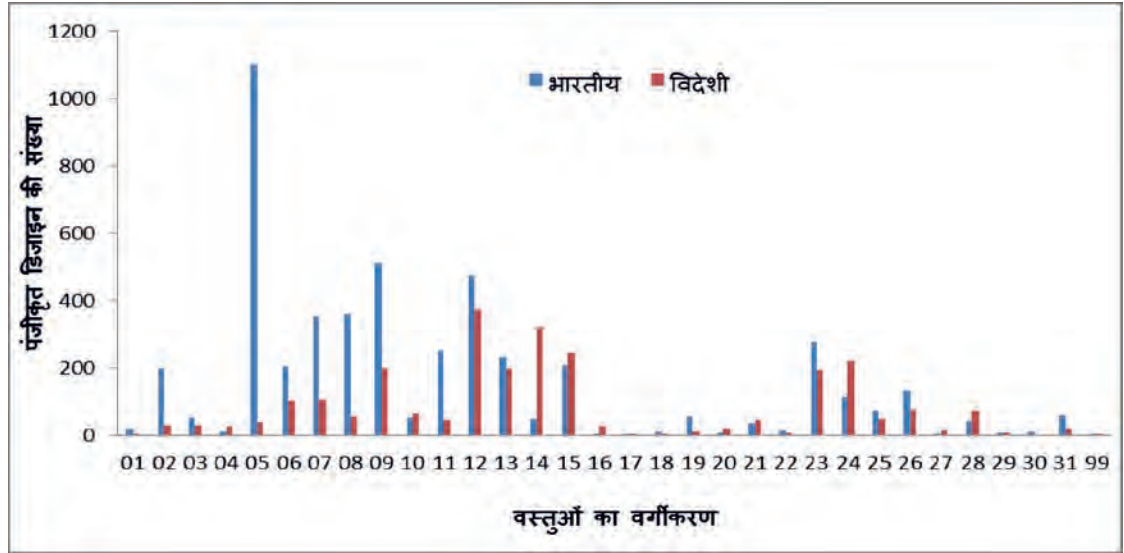
भारत से उद्गमित आवेदनों में से अधिकतम आवेदन वस्त्र अंश वस्तुएं, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ के तहत दाखिल किए गए जिसके बाद यातायात या उत्तोलन के साधन व यातायात के लिए पैकेज या कंटेनर अथवा समान का रख रखाव के तहत दाखिल हुए। दूसरी तरफ विदेशों से उद्गमित आवेदनों में मुख्यतः रिकॉर्डिंग, संचार या सूचना प्राप्ति उपकरण, यातायात या उत्तोलन के साधन व मशीन के क्षेत्र से थे। भारत और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:





वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

इसी प्रकार, भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया है।



विदेशों से उद्गमित आवेदनों के संदर्भ में यू.एस.ए. आवेदनों की अधिकतम संख्या (870) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः कोरिया गणतंत्र (514), जापान (437), जर्मनी (302), यू.के. (272), फ्रांस (216), चीन (157), स्विट्जरलैंड (154), इटली (125), नीदरलैंड (120), स्वीडन (93), फिनलैंड (53), डेनमार्क (22), आस्ट्रेलिया (22), बेलजियम (19), आस्ट्रिया (17) और कनाडा (11) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत भारत एवं अन्य कन्वेंशन देशों के बीच पारस्परिक व्यवस्था के तहत 3199 आवेदनों ने प्रायिकता दावे दाखिल किए।

अग्रणी विदेशी कम्पनियाँ जिन्होंने आवेदन दाखिल किए वे थीं- सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कं. लि.(244), एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक. (182), कोनिकलिके फिलिप्स एन.भी. (109), माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन (82), जिलेट कंपनी (64), रेनॉल्ट एस.ए.एस. (63), होंडा मोटर कम्पनी लिमिटेड (61), रिकेट बेन्किसेर (ब्रांड्स) लि. (42), डार्ट इंडस्ट्रीज इंक (33) और ऑडी एजी (32) आदि।

इसी प्रकार, भारतीय कम्पनियों में सिद्धि विनायक नोट्स एंड प्रिंट्स प्र.लि.(521), साव्यसाची कोट्यूर (212), मा डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (192), मिस्टर सिद्धार्थ



बिन्द्रा (189), मारुति सुजुकी इंडिया लि. (98), हीरो मोटोकॉर्प लि. (79), एक्शन/कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट लि. (70), मेरिल हेल्थकेयर प्रा. लि. (68), बजाज ऑटो लिमिटेड (54) और जी.एल. मोड्यूलर प्रा.लि. (51) आदि अग्रणी रहे।

3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षण:

प्रतिवेदन अवधि के दौरान डिजाइन के पंजीकरण हेतु 9426 आवेदनों का परीक्षण किया गया जिसमें से 7545 आवेदनों के लिए परीक्षण रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या 7904 थी। पंजीकरण के अतिरिक्त 119 आवेदनों का निष्पादन अस्वीकृति और परित्याग के माध्यम से हुआ।

4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार [धारा 11(2) के तहत]:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए 1,190 आवेदन प्राप्त किए गए। 713 पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण प्रतिवेदन वर्ष के दौरान किया गया। हालाँकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 80 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 07 आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

5. विविध कार्यवाहियाँ:

पंजीकृत डिजाइन का निरस्तीकरण [धारा 19 के तहत]: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए 80 आवेदन दाखिल हुए। वर्ष के दौरान 56 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 15 मामलों पर याचिका अनुमत की गई और 41 मामलों में याचिका खारिज कर दी गई।

जनता द्वारा निरीक्षण [नियम 38 के तहत]: पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु 53 याचिका प्राप्त की गई।

नाम और पते आदि में परिवर्तन [नियम 31 के तहत]: वर्ष के दौरान, नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु 1405 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 681 मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन [नियम 29 के तहत]: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु 32 अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान वर्ष के दौरान ही कर दिया गया।

नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियाँ: प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 544 अनुरोध दाखिल किए गए और 839 के लिए सत्यापित प्रतियाँ जारी की गईं।

6. प्रवृत्त डिजाइन: प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या **68481** रही।



परिशिष्ट- क

2015-16 के दौरान डिजाइन संबंधी अर्जित राजस्व			
प्रलेखों का विवरण	संख्या	शुल्क (रु.)	राशि (रु.)
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	11108	1000, 2000, 4000	3,51,29000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्याधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	1190	2000, 4000, 8000	90,36000
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	80	1000, 2000, 4000	27,5000
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	80	1500 3000, 6000	4,18500
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	544	500, 1000, 2000	12,48500
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		अनुसूची के अनुसार	9665306
कुल योग			5,57,72,306

परिशिष्ट- ख

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	दाखिल			पंजीकृत		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
2011-12	5292	3081	8373	4162	2428	6590
2012-13	5428	2909	8337	4662	2590	7252
2013-14	5530	3003	8533	4330	2848	7178
2014-15	6505	2822	9327	4726	2421	7147
2015-16	7895	3213	11108	5532	2372	7904



अध्याय - VI

व्यापार चिह्न

1. परिचय

यह अध्याय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 57वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम 1940 के तहत स्थापित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री वर्तमान में व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 के तहत कार्य करती है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री मुख्यतः व्यापार चिह्न रजिस्टर के पंजीकरण व रख रखाव के लिए उत्तरदायी है व भारत में व्यापार चिह्न विषयक मामलों के संदर्भ में संसाधन कार्यालय के रूप में कार्य करता है। रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरूकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग मल्टी क्लास आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है। रजिस्ट्री विस्तृत ई-फाइलिंग सेवा गेटवे के माध्यम से वेब आधारित सेवाएं भी प्रदान करती है जिसमें सभी व्यापार चिह्न आवेदन और अन्य व्यापार चिह्न फॉर्म तथा शुल्क के ई-पेमेंट की सुविधा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त व्यापार चिह्न रजिस्ट्री पर व्यापार चिह्न से संबंधित वायपो की स्थायी समिति के व्याख्यानों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसरण करने के साथ ही डोमेन नाम तथा इंटरनेशनल नॉन प्रोपरायटरी नामों जैसे उभरते मुद्दों के लिए सुझाव प्रदान करने की जिम्मेदारी भी है।

वर्ष 2015-2016 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2015-2016 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 में दाखिल 2,10,501 आवेदनों की तुलना में वर्ष 2015-





16 में दाखिल आवेदनों की संख्या 2,83,060 रही जो 72,559 आवेदनों की वृद्धि दर्ज करती है। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या परिशिष्ट-1 में दी गई है।

क्रम संख्या	गतिविधियाँ	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	2,00,005	2,10,501	2,83,060
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	67,796	81,959	1,17,408
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	67,876	41,583	65,045
4.	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित उत्तर-परीक्षण आवेदनों की संख्या	36,880	42,069	25,617
5.	पंजीकरण का नवीकरण किए जानेवाले चिह्नों की संख्या	32,202	43,889	58,160
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	19,856	10,051	11,075
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1983 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	3,825	3,257	8,185

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति:

भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015 -2016 में भारतीयों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या 2,67,390 थी तथा विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 15,670 थी।



2011-12 से 2015-16 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्ति

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2011-12	1,69,602	13,986	1,83,588
2012-13	1,79,436	14,780	1,94,216
2013-14	1,84,140	15,865	2,00,005
2014-15	2,02,654	7,847	2,10,501
2015-16	2,67,390	15,670	2,83,060

3. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष 2015-16 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे ज्यादा आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधी, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थ आदि) के लिए प्राप्त हुए हैं।

व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदनों के वर्गानुसार वितरण का विवरण

वर्ग	वस्तुएं	दाखिल आवेदन	कुल दाखिल आवेदनों का %
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	4567	1.45
2	पेंट और वार्निश	1843	0.59
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	10907	3.47
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	1731	0.55
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	28933	14.93
6	अन-रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	3938	1.25





33	वाइन स्पिरिट और मद्य पेय	1645	0.52
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	2072	0.66
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	31807	10.11
36	बीमा वितीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	5651	1.80
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	5402	1.72
38	दूरसंचार	4433	1.41
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4169	1.32
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1508	0.48
41	शिक्षा, प्रशिक्षण देना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	16251	5.16
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	11873	3.77
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	8544	2.71
44	चिकित्सा सेवाएं ; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	5654	1.80
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	3736	1.19
	कुल	314717	100

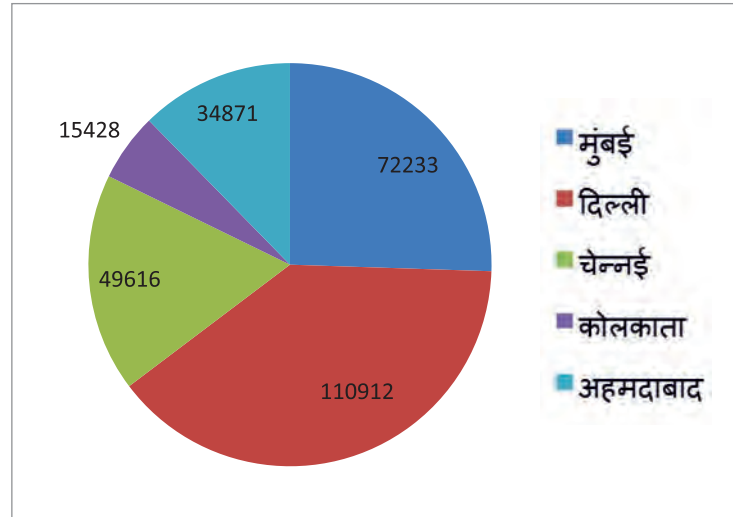
टिप्पणी: बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है परंतु जैसे आवेदनों के लिए एकल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वर्गानुसार आवेदन संबंधी उपर्युक्त सूचना के लिए बहुवर्ग आवेदनों में प्रत्येक वर्ग को अलग वर्ग माना गया है।





4. शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्ति:

वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या (1,10,912) में आवेदन दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमशः मुंबई (72,233), चेन्नई (49,616), अहमदाबाद (34,871) एवं कोलकाता (15,428) का स्थान आता है।



5. व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँ:

वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 65,045 रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान 41,583 चिह्न पंजीकृत किए गए थे। दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या 10,88,174 थी।

वर्ष के दौरान नवीकृत किए गए पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या 58,160 रही। पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन करने हेतु 19,422 अनुरोध प्राप्त हुए और वर्ष 2015-16 के दौरान 11,075 अनुरोध निष्पादित कर दिए गए।



इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए या विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु 8,185 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत 4,695 प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के 81,959 विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 1,17,408 आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति **परिशिष्ट II** में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने अधिनियम और नियम के अधीन विधिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यतः विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थीं। वर्ष 2015-16 के दौरान विरोध की सूचना और रजिस्टर के परिशोधन हेतु 18,910 आवेदन दाखिल किए गए और ऐसे 38,846 मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों के विवरण **परिशिष्ट III** में दिया गया है।

6. पंजीकृत व्यापार चिह्न का वर्गानुसार विवरण

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2015-16 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग-5 के अंतर्गत 10,303 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए जो कुल पंजीकरण का 15.20% है, जिसके बाद वर्ग-35 आता है जो 6.89% है। हालाँकि, विविध वर्गों में 2,151 व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए जो कुल पंजीकृत चिह्न का लगभग 3.17% है।

पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरण

वर्ग	वस्तुएं	पंजीकृत व्यापार चिह्न	कुल पंजीकरण का प्रतिशत
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान-कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	1483	2.084





2	पेंट और वार्निश	538	0.756
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	2414	3.392
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	478	0.672
5	भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	8599	12.083
6	अन-रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	1275	1.792
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	2243	3.152
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	458	0.644
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	4552	6.396
10	शल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	951	1.336
11	प्रकाशन साधित्र, तापक आदि	1884	2.647
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	1321	1.856
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	136	0.191
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	923	1.297
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	159	0.223
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	2693	3.784
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	881	1.238
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े से बनी वस्तुएं आदि	709	0.996
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	1337	1.879
20	फर्नीचर, आईने आदि	799	1.123

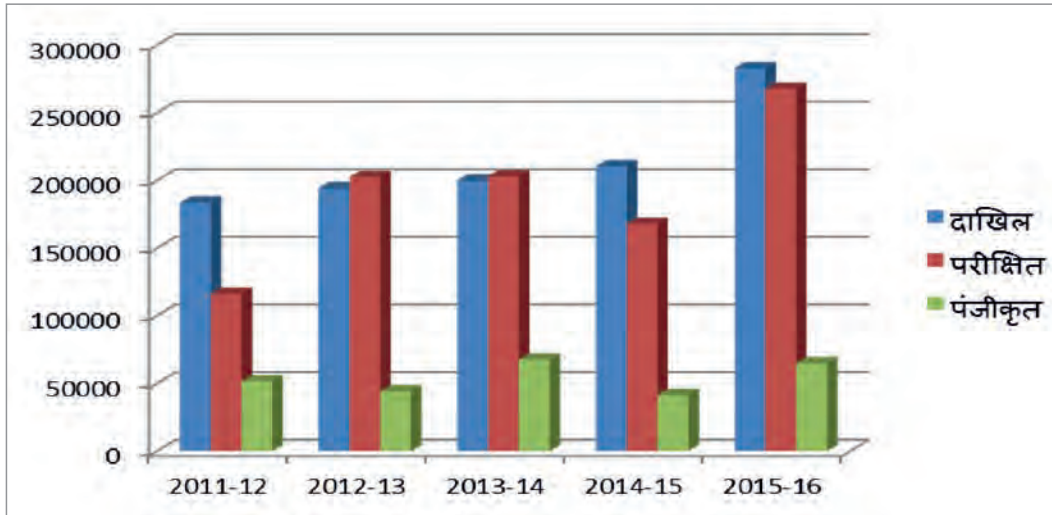


21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	790	1.110
22	रस्सी, सुतली आदि	253	0.356
23	सूत और धागे	292	0.410
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	1225	1.721
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	3504	4.924
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	299	0.420
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	234	0.329
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	666	0.936
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	1581	2.222
30	काँफी, चाय, कोको आदि	3386	4.758
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों में अंतर्गत नहीं हैं	1333	1.873
32	बीयर, एले और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं हैं	1188	1.669
33	वाइन, स्प्रिट और मद्य पेय	518	0.728
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	780	1.096
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	5592	7.858
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	1675	2.354
37	भवन निर्माण, मरम्मत, संस्थापन सेवाएं	1831	2.573
38	दूरसंचार	1010	1.419
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	950	1.335
40	सामग्री का बहिस्त्राव	414	0.582



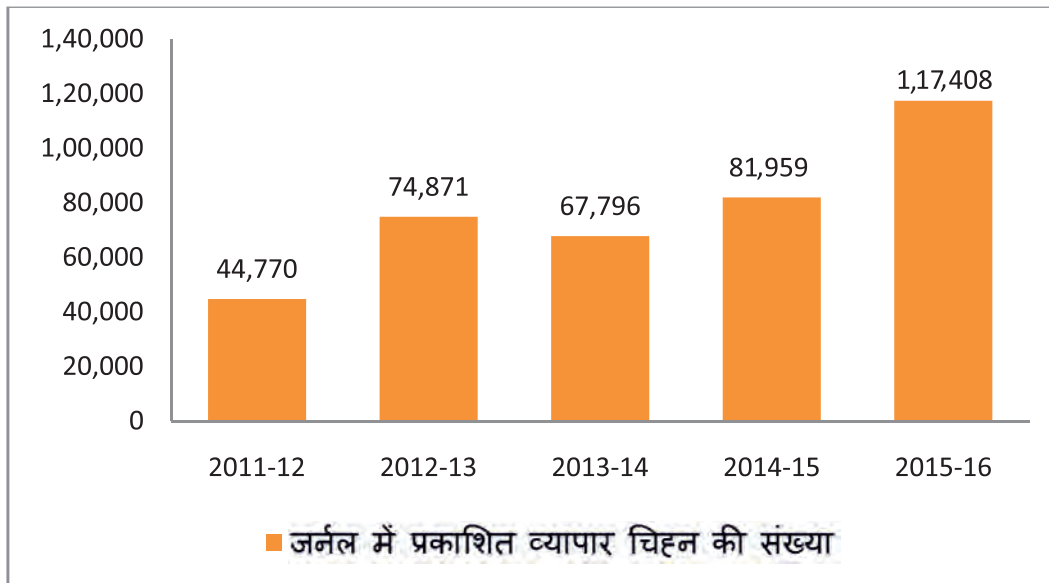


पिछले 5 वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति की ग्राफीय प्रस्तुति



परिशिष्ट- II

पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित व्यापार चिह्न

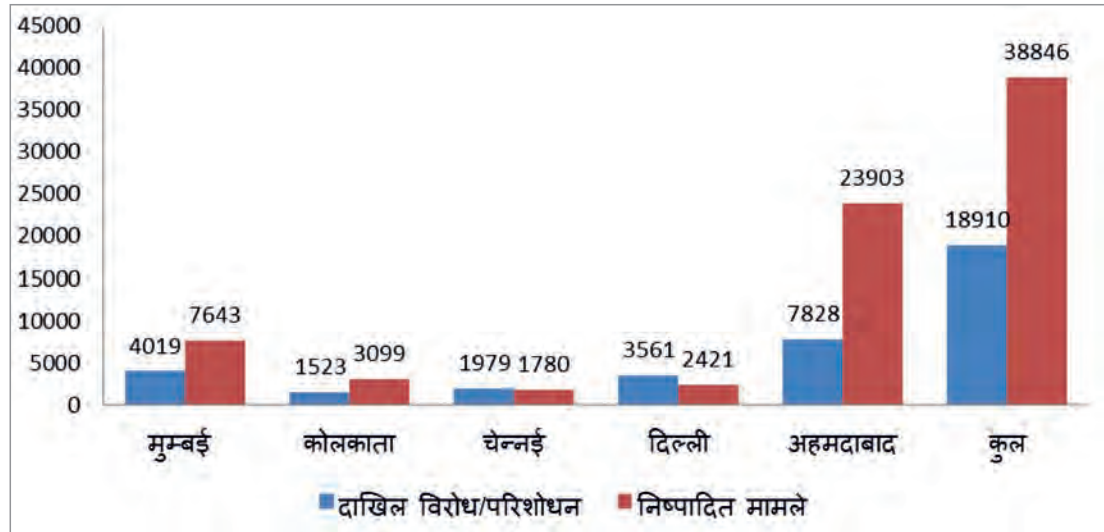




परिशिष्ट-III

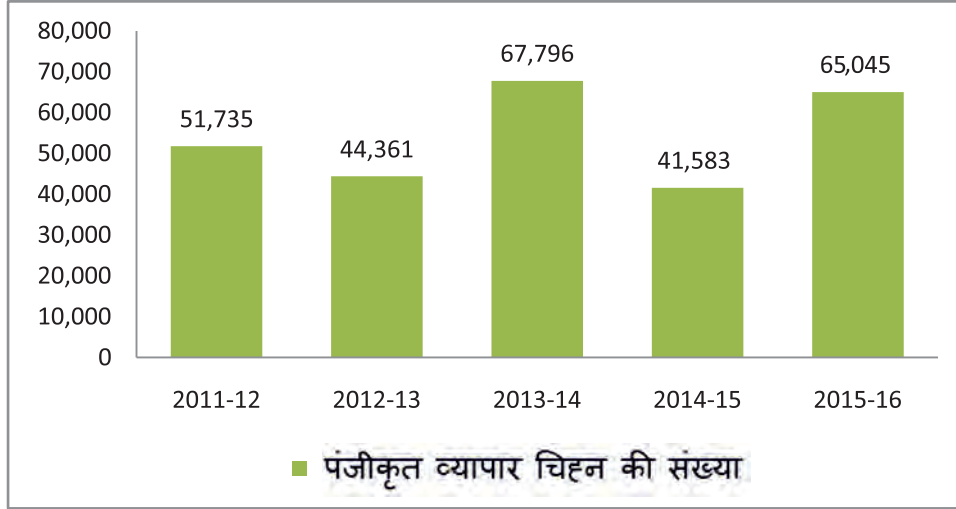
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

क्रम संख्या	सुनवाई का स्थान	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
1.	मुम्बई	4019	7643
2.	कोलकाता	1523	3099
3.	चेन्नई	1979	1780
4.	दिल्ली	3561	2421
5.	अहमदाबाद	7828	23903
	कुल	18910	38846





पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न



व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के मैड्रिड प्रोटोकॉल से सहमति

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित प्रावधान 8 जुलाई, 2013 से भारत में लागू हुए हैं।

भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री उन भारतीय आवेदक जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अपने व्यापार चिह्न हेतु अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण चाहते हैं उनके लिए **उद्गम कार्यालय** व जो विदेशी आवेदक मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अपने व्यापार चिह्न का भारत में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण द्वारा संरक्षण चाहते हैं उनके लिए **नामित करार पक्ष कार्यालय** का कार्य करता है। ये कार्य सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही किए जाते हैं।

उद्गम कार्यालय के रूप में: इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से, यह कार्यालय;

- भारतीय उद्यमियों से अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना एवं व्यापार चिह्न रजिस्ट्री से व्यापक ई-फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से ऐसे आवेदनों के बारे में उन से ऑनलाइन संवाद स्थापित करना;
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित एवं प्रमाणित करना और उन्हें वायपो को प्रेषित करना;
- भारत द्वारा अग्रेषित अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वायपो द्वारा भेजी गई अनियमितताओं का उत्तर देना;





- भारत से उद्गम होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के साथ-साथ एफटीपी सर्वर द्वारा भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में वायपो से पत्राचार

नामित करार पक्ष कार्यालय के रूप में: इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से यह कार्यालय

- वायपो द्वारा अधिसूचित भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का विवरण हमारी राष्ट्रीय प्रणाली में शामिल करता है;
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में वायपो द्वारा आगे जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार हमारे राष्ट्रीय डाटाबेस को अद्यतन करता है;
- अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का हमारे देश के कानून के अनुसार परीक्षण करना, स्वीकृत मामलों को राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित करना और आपत्ति वाले मामलों में वायपो को अनंतिम अस्वीकृति प्रेषित करता है;
- प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय डेसिगनेशन के विरुद्ध तीसरे पक्ष का विरोध प्राप्त करना और विरोध के आधार पर वायपो को अनंतिम अस्वीकृति प्रेषित करता है;
- हमारे देश के कानून के अनुसार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के धारकों की तरफ से अनंतिम अस्वीकृति के विरुद्ध दाखिल जवाब पर कार्रवाही करना और वायपो को अपना अंतिम निर्णय प्रेषित करता है;
- भारत को नामित किए गए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण संबंधी किसी सक्षम प्राधिकारी का उत्तरोत्तर निर्णय वायपो को प्रेषित करता है;

वर्ष 2015-16 के अंत तक वायपो ने भारत में व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए **23,632** अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया। **11,600** चिह्न के संबंध में वायपो को भारत में तदनरूपी चिह्न की संरक्षा की औपबंधिक अस्वीकृति की सूचना भारतीय विधान के अनुसार वैसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के परीक्षण के बाद दी गई है; और सभी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद **924** चिह्न के लिए संरक्षा अनुदान करने की सूचना दी गई।

वर्ष 2015-16 के अंत तक, भारतीय कार्यालय ने मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु **385** आवेदन प्राप्त किए जिनमें से **362** आवेदनों का सत्यापन कर वायपो को अग्रेषित किया गया है। इन आवेदनों में से **260** आवेदनों का पंजीकरण वायपो के स्तर पर कर दिया गया है और वैसे चिह्न की संरक्षा के संबंध में अंतिम निर्णय करने के लिए नामित करार करने वाले पक्षों के कार्यालयों को प्रेषित किया गया है।





अध्याय - VII

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण और बेहतर संरक्षा प्रदान करना तथा वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण एवं संरक्षा) अधिनियम, 1999 का प्रशासन करना है जो 15 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुआ। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है।

रजिस्ट्री कार्यालय ने 15 सितम्बर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन ग्रहण करना प्रारंभ किया। रजिस्ट्री कार्यालय ने 31 मार्च, 2016 तक कुल 543 (पाँच सौ तेतालीस) भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त किए हैं।

रजिस्ट्री कार्यालय ने मई, 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन भी प्राप्त करने प्रारंभ किए हैं और वित्तीय वर्ष के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय ने कुल 2349 (दो हजार तीन सौ उनचास) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल 261 (दो सौ इकसठ) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। कुल 1184 (एक हजार एक सौ चौरासी) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

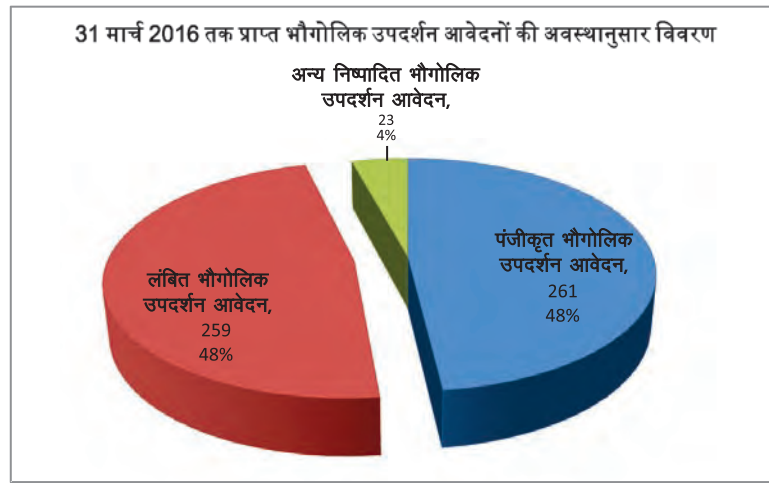
रजिस्ट्री कार्यालय भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इस दौरान चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्ध उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं शराब क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।





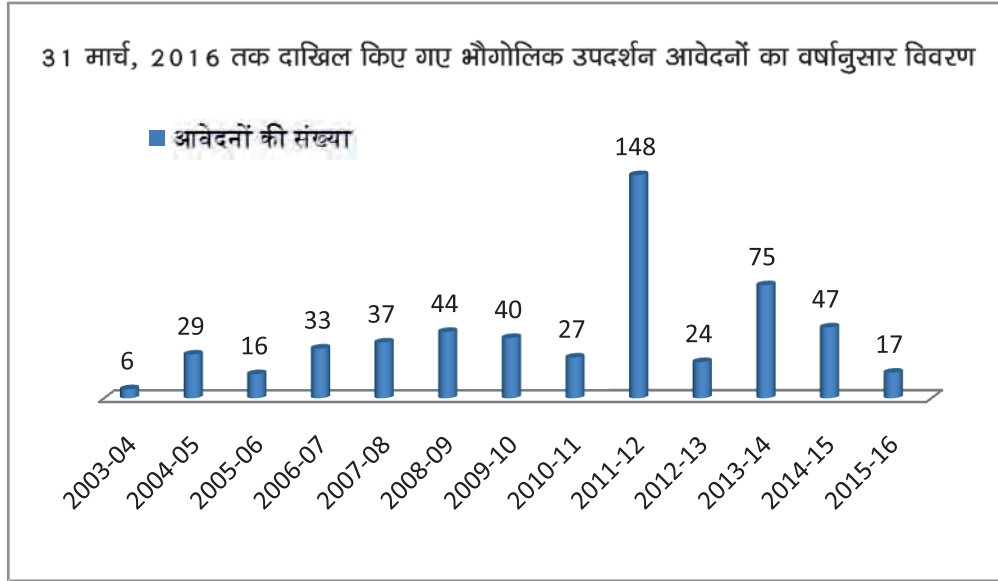
31 मार्च, 2016 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदन की स्थिति

दाखिल भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	543
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	278
पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की कुल संख्या	261
लंबित भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	259
अन्य निष्पादित भौगोलिक उपदर्शन आवेदन	23



31 मार्च, 2016 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदन का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003-04	6
2004-05	29
2005-06	16
2006-07	33
2007-08	37
2008-09	44
2009-10	40
2010-11	27
2011-12	148
2012-13	24
2013-14	75
2014-15	47
2015-16	17



भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	257	167
कृषि	105	68
विनिर्मित	148	18
खाद्य पदार्थ	27	7
प्रकृत	6	1
कुल	543	261





31 मार्च, 2016 तक भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

- 31 मार्च, 2016 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण
- 31 मार्च, 2016 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण



31 मार्च, 2016 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

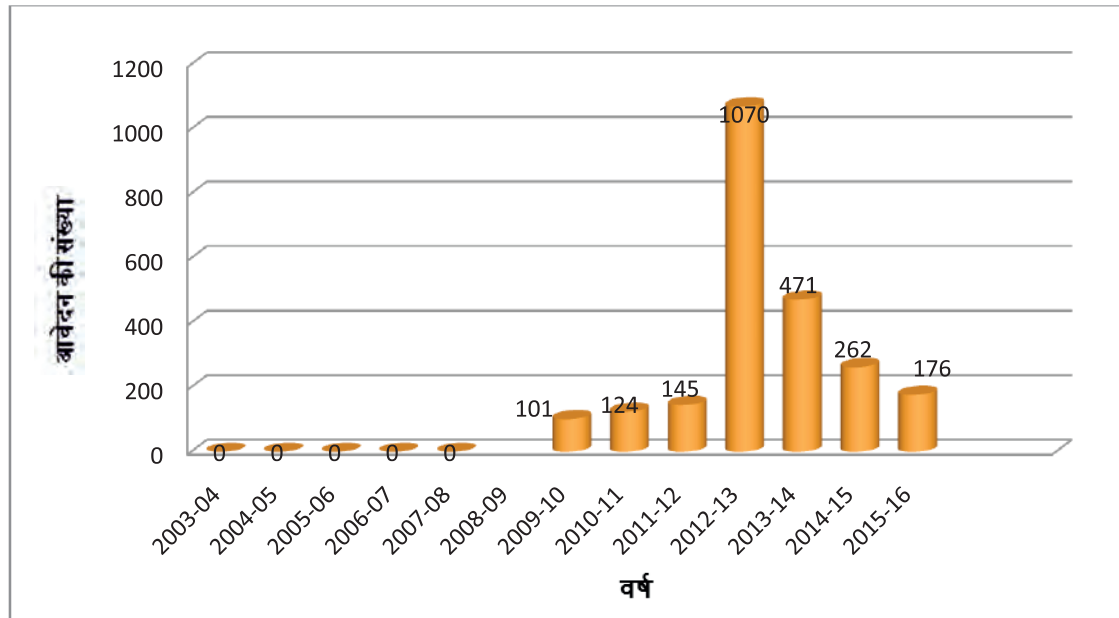
राज्य	भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	12
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	5
बिहार	5
छत्तीसगढ़	5
गोवा	1
गुजरात	12
हिमाचल प्रदेश	6
भारत (बासमती)	1
जम्मू एवं कश्मीर	6
कर्नाटक	38
केरल	26
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	17
मणिपुर	4



31 मार्च, 2016 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदन की संख्या
2003-04	0
2004-05	0
2005-06	0
2006-07	0
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	101
2010-11	124
2011-12	145
2012-13	1070
2013-14	471
2014-15	262
2015-16	176

प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण





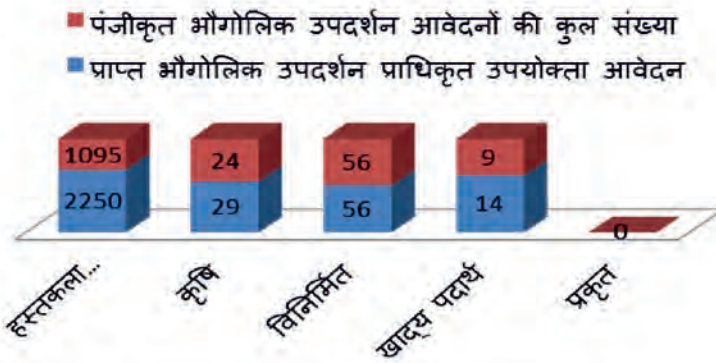
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पंजीकृत	1184
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या परीक्षण	1124
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या पूर्व-परीक्षण	40
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विज्ञापित	0
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या विरोध	1
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	2349

31 मार्च, 2016 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	2250	1095
कृषि	29	24
विनिर्मित	56	56
खाद्य पदार्थ	14	9
प्रकृत	0	0
कुल	2349	1184

31 मार्च, 2016 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की वस्तुओं के अनुसार विवरण





अध्याय - VIII

पेटेंट सूचना पद्धति एवं
राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान
(आरजीएनआईआईपीएम)



परिचय

राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि का राष्ट्रीय केन्द्र है। यह संस्थान एकस्व एवं अभिकल्प परीक्षकों, आईपीओ अधिकारियों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसाइयों, देश के बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण देने, उपयोक्ता समुदायों को मूलभूत शिक्षा, उपयोक्ता समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के साथ-साथ किसी राष्ट्र के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकारी संबंधी गतिविधियां विगत कई वर्षों से देश में निरंतर उत्थान दर्शाती हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, उपयोग और अर्थपूर्ण दोहन में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। इस कारण बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषयक ज्ञान में सुधार के लिए एक प्रभावी साधन की आवश्यकता है और आरजीएनआईआईपीएम सार्वजनिक आईपीआर कार्यक्रमों के संचालन से सामान्य व्यक्ति की दक्षता अद्यतन करता है। राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) और पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) दोनों भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं और सिविल लाइंस, नागपुर में स्थित एक ही भवन में अवस्थित हैं।



आरजीएनआईआईपीएम, बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में देश में अपनी तरह का अकेला राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र है जिसका गठन विभिन्न उपयोक्ता समूहों को गुणता-सम्पन्न प्रशिक्षण और शिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया है।

उद्देश्य

- ▶ बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की सभी आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान और पूरा करना तथा प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना,
- ▶ परीक्षक, एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न तथा भौगोलिक उपदर्शन, कॉपीराइट के अधिशासियों का प्रशिक्षण,
- ▶ बौद्धिक सम्पदा व्यवसासियों, बौद्धिक सम्पदा प्रबंधकों और अनुसंधान एवं शोध वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थानों, व्यक्तियों का प्रशिक्षण,
- ▶ विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों सहित बौद्धिक सम्पदा प्रणाली के उपयोक्ताओं में सामान्य जागरूकता और समझदारी बढ़ाना,
- ▶ उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,
- ▶ देश में सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा हितधारकों के लिए स्वयं और प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना,
- ▶ बौद्धिक सम्पदा जागरूकता बढ़ाना,

राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा से संबंधित प्रशिक्षण देना और जागरूकता सृजित करना है। यह संस्थान बौद्धिक सम्पदा के विकास, सृजन, उपयोग और दोहन में सहायता प्रदान करता है। आरजीएनआईआईपीएम, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ बौद्धिक सम्पदा (आईपी) पद्धति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है जो वैश्विक नियमों के अनुसार हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आरजीएनआईआईपीएम निम्न के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है

- ▶ नवनियुक्त पेटेंट परीक्षक,
- ▶ पेटेंट परीक्षकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- ▶ नियंत्रकों के लिए विधायी प्रशिक्षण,





- ▶ बौद्धिक सम्पदा पर अल्पकालिक जन प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- ▶ जागरूकता कार्यक्रम,

राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम), नागपुर बौद्धिक सम्पदा प्रणालियों के वास्तविक और संभावित उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पदा अधिकार अर्थात एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, कॉपी राइट विषयक कई सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों से उद्योग जगत से जुड़े व्यवसायी, स्टार्टअप, विधि-वृत्तिक तथा संभावित पेटेंट/बौद्धिक सम्पदा अधिकार एजेंट, अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक/तकनीकी/अनुसंधान एवं विकास संगठन, उद्योगों के प्रबन्धक व टेक्नोक्रेट्स, लघु तथा मध्यम व्यवसायी, विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग, केन्द्र तथा राज्य सरकार/अन्य सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग, अन्य आविष्कारक तथा रुचि रखनेवाले आम लोग लाभान्वित होते हैं।

परीक्षकों के लिए विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषयक कई सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के दौरान संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों के दौरान अच्छी जन प्रतिक्रिया देखी गई और संस्थान ने उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त किया।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान ने वर्ष के दौरान 55 सार्वजनिक कार्यक्रम संचालित किए जिनमें 1-दिवसीय सात (7) कार्यक्रम, 2-दिवसीय बारह (12) कार्यक्रम, 3-दिवसीय सात (7) कार्यक्रम, 5-दिवसीय पाँच (5) कार्यक्रम, आम जनता के लिए उन्नीस (19) जागरूकता/सेमिनार कार्यक्रम और विभागीय सहायक नियंत्रकों के लिए दो (2) कार्यक्रम शामिल हैं। 2015-16 के दौरान जन प्रशिक्षण कार्यक्रम से रु. 25,63,900/- का राजस्व अर्जित किया गया।

संकाय के सदस्य

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री और अग्रणी पेटेंट एटॉर्नी, प्रोफेसर आदि सहित देश के सुख्यात संगठनों से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विशेषज्ञ थे।





इस कार्यक्रम के अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट शोध सूचना शामिल है।

2] पेटेंट आवेदन की प्रक्रिया और उसकी कार्यवाही [2-दिवसीय]

बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, पेटेंट आवेदन के प्रकार, अपेक्षित फॉर्म और शुल्क, ई-फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया।



3] पेटेंट आवेदन विनिर्देश लेखन/प्रारूपन [3-दिवसीय]

अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, दावा और विनिर्देश प्रारूपन, प्रारूपन की पूर्व आवश्यकता, दावों की व्याख्या, पेटेंट आवेदन दाखिल करने पर अभ्यास और अन्य दस्तावेज तथा दावों का प्रारूपन।





4] भारत में पेटेंट प्रणाली [5-दिवसीय]

पेटेंट प्रणाली का इतिहास, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीयपरिदृश्य एवं दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख, दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, आपत्ति, अतिलंघन, अनिवार्य लाईसेंसिंग एवं प्रौद्योगिकी, पेटेंट सूचना एवं अन्वेषण।



5] डिजाइन, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन [2-दिवसीय]

बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय, औद्योगिक डिजाइन की संरक्षा की आवश्यकता, डिजाइन पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, औद्योगिक डिजाइन अधिनियम द्वारा क्या संरक्षित नहीं है, डिजाइन पंजीकरण हेतु अवधि और शुल्क।

व्यापार चिह्न और इसके पंजीकरण की प्रक्रिया, लाईसेंसिंग तथा विरोध, वर्गीकरण, व्यापार चिह्न का अतिलंघन, निदान व अन्य कार्यवाहियाँ।

भौगोलिक उपदर्शन व भारतीय एवं विदेशी भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु कार्यवाही।





पेटेंट सूचना पद्धति

भारत सरकार ने 1980 में नागपुर में पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद संकलन प्राप्त करने और रखने ताकि अनुसंधान एवं शोध संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता को पूरा व अन्वेषण सेवाओं द्वारा पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध करने तथा पेटेंट विनिर्देशों की प्रति आपूर्ति के उद्देश्य से की।

पेटेंट सूचना पद्धति की सेवाएँ

पेटेंट सूचना पद्धति द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची निम्नवत है:

आधुनिकीकृत सेवा

- आधुनिकीकृत सेवा का पूर्वावलोकन प्रदान करता है।
- अन्वेषण पेटेंट दस्तावेज के सार तथा संदर्भगत आँकड़े प्रदान करता है।
- अधिभार: ₹ 2000+ ₹ 8 प्रति पृष्ठ

संदर्भगत अन्वेषण

- अन्वेषित पेटेंट दस्तावेज के संदर्भगत आँकड़े उपलब्ध कराता है।
- आविष्कारक का नाम, आवेदक का नाम, वर्गीकरण संकेत सहित एक या अधिक उपयुक्त खोज शब्दावली का प्रयोग करता है।
- अधिभार: ₹ 500+₹ 8 प्रति पृष्ठ

अंग्रेजी समरूपी पेटेंट अन्वेषण

- अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के पेटेंट के लिए अंग्रेजी भाषा समरूप पेटेंट का निर्धारण किया जाता है।
- अधिभार: ₹ 50/- एक अंग्रेजी भाषा समरूप पेटेंट का निर्धारण करने के लिए।

पेटेंट परिवार अन्वेषण

- पेटेंट परिवार के सभी सदस्यों के संदर्भगत आँकड़े उपलब्ध कराया जाता है।
- अधिभार: ₹ 50/- प्रति परिवार सदस्य।





सहायक अन्वेषण

- उपयोक्ताओं को अन्वेषण संचालित करने के लिए डाटाबेस का उपयोग करने की अनुमति होती है।
- अन्वेषण करने में सामान्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अधिभार: रु 250/- प्रति घंटा।

पेटेंट प्रति आपूर्ति सेवा

पेटेंट सूचना पद्धति पेटेंट दस्तावेज के पूर्ण पाठ की छाया प्रति उपलब्ध कराती है जो पीआईएस में उपलब्ध हैं तथा भारतीय पेटेंट विनिर्देश की छाया प्रति भी पीआईएस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।





अध्याय - IX

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

परिचय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और महानियंत्रक कार्यालय ने द्विपक्षीय स्तर के साथ-साथ बहुपक्षीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, विभिन्न क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान एवं आपसी सहयोग के अवसर प्रदान किए हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकारियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे पेटेंट नियम पर स्थायी समिति (एससीपी), (एससीटी), पीसीटी कार्यकारी समूह, मैड्रिड कार्यसमूह, अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बैठक (एमआईए) आदि में भाग लिया। कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन ने घरेलू स्तर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में अपने सतत प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2015-16 में जहाँ एक तरफ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और महानियंत्रक कार्यालय के बीच कई सहयोगी गतिविधियाँ देखी गईं वहीं दूसरी तरफ वायपो, यूरोपीय पेटेंट कार्यालय, जापान पेटेंट कार्यालय, ऑफिस फॉर हार्मोनाइजेशन इन द इंटरनल मार्केट (ओएचआईएम) के साथ कई सहयोगी गतिविधियां देखी गईं। 24 सितम्बर, 2013 को वायपो की सामान्य सभा के दौरान सहचर बैठक में भारत ने पाँच बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा तैयार रोड मैप पर हस्ताक्षर किए जिस पर अन्य चार देशों ने दक्षिण अफ्रीका में मई 2013 में हस्ताक्षर किए थे। यह अध्याय रिपोर्ट की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में हुई प्रगति से संबंधित है।

1. भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य:

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट सहयोग संधि के तहत **15 अक्टूबर, 2013** से अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में कार्य आरंभ कर दिया है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आईएसए/आईपीईए के रूप में कार्य करने से संबंधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013, 15 अक्टूबर, 2013 को अस्तित्व में आ गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करने के लिए बौद्धिक सम्पदा कार्यालय ने **31.03.2016** तक कुल 1364 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त किए हैं। 31.03.2016 तक **1141** अंतर्राष्ट्रीय





खोज रिपोर्ट जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में कार्यालय ने 35 अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षण की मांग प्राप्त की है जो परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

2. मैड्रिड प्रोटोकॉल

भारतीय व्यापार चिह्न रजिस्ट्री मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अपने व्यापार चिह्न का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण करवाना चाह रहे भारतीय आवेदकों के लिए **उद्गम कार्यालय** का कार्य करता है और जो विदेशी आवेदक मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण द्वारा अपने व्यापार चिह्न का संरक्षण चाहते हैं उनके लिए **नामित करार पक्ष कार्यालय** का कार्य करता है।

3. भारत और यूरोपियन युनियन के बीच बौद्धिक संपदा समन्वय:

यूरोपियन युनियन भारत के व्यापार विकास के लिए क्षमता संवर्द्धन प्रयास परियोजना (सीआईटीडी) का समर्थन करता है।

- सीआईटीडी के तहत यूरोपियन कमिशन और भारत सरकार ने 2015-17 तक की अवधि के लिए ईयू इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी कोऑपरेशन (आईपीसी-ईयूआई) परियोजना को लागू करने पर सहमत हुए। दिसम्बर 2014 में, ईयू ऑफिस फॉर हार्मोनाइजेशन इन द इन्टर्नल मार्केट (ओएचआईएम) [जिसने हाल ही में अपना नाम बदलकर *यूरोपियन युनियन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी ऑफिस (ईयूआईपीओ)* कर लिया है] ने परियोजना क्रियान्वित करने की एजेंसी के रूप में कार्य करने पर सहमति दी। वर्ष 2015 के दौरान, ओएचआईएम (ईयूआईपीओ) के कई मिशन ने भारतीय कार्यालय का दौरा किया। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2016 के महीने में उनके कार्यालय एलिकांटे, स्पेन का दौरा किया। भारतीय कार्यालय और ईयूआईपीओ विशेषज्ञों के बीच व्यापार चिह्न और डिजाइन के पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रसंस्करण में शामिल विभिन्न गतिविधियों का सर्वोत्तम कार्य व्यवहार के आदान-प्रदान के लिए कई बैठकें हुई हैं।



4. वायपो सामान्य सभा के दौरान सहचर बैठकें: वायपो सामान्य सभा की बैठकों के दौरान महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न के साथ निम्नलिखित सहचर बैठकें हुईं।

(क) यूकेआईपीओ: यूकेआईपीओ के मुख्य कार्यकारी श्री जॉन एल्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ पेटेंट निदेशालय और अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री राजीव अग्रवाल, तत्कालीन महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के साथ 5 अक्टूबर, 2015 को बैठक की। यहाँ चर्चा के केंद्र में दोनों कार्यालयों के बीच बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित सूचना के हस्तांतरण और साझा करने के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ाना था।

(ख) ओएचआईएम: द ऑफिस फॉर हार्मोनाइजेशन इन द इंटरनल मार्केट (ओएचआईएम) ने सीजीपीडीटीएम और ओएचआईएम के बीच आईपी के क्षेत्र, जिसमें सीआईटीडी परियोजना की प्रगति शामिल थी, उस विषय पर परस्पर समन्वय बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की। अध्यक्ष श्री एंटोनियो कैंपिनस ने ओएचआईएम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री राजीव अग्रवाल, तत्कालीन महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने किया। बैठक मुख्यतः भारत में एक परियोजना का कार्यान्वयन करना था जो दोनों कार्यालयों के बीच क्षमता निर्माण व समन्वय गतिविधियां बढ़ाने के संबंध में था जो (i) (i) व्यापार चिह्न सूचना डाटाबेस, (ii) डिजाइन डाटाबेस (वर्गीकरण), (iii) टीएमव्यू का डाटाबेस, (वर्तमान में 43 देशों और 23 भाषाओं में जारी), (iv) गुणता प्रबंधन प्रणाली, (v) सर्वोत्तम व्यवहार का आदान-प्रदान और (vi) परीक्षण दिशानिर्देश इत्यादि के संदर्भ में हैं।





- (ग) **स्वीडन पेटेंट और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय:** सुश्री सुशान अस शिवबर्ग, डायरेक्टर जेनरल और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ स्वीडन के कार्यालय में बैठक हुई। महानियंत्रक और डीजी स्वीडीश कार्यालय साधारण सहमति जापन और विस्तृत कार्य योजना बनाने पर सहमत हुए ताकि दोनों देशों के बीच बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहमति स्थापित हो सके।
- (घ) **इजरायल आईपीओ:** श्री असा क्लिंग, आईएलपीओ के अध्यक्ष और डॉ माइकल बार्ट, पीसीटी विभाग के निदेशक ने सीजीपीडीटीएम के साथ दोनों देशों के बीच भविष्य में संभावित समन्वय का पता करने के लिए एक बैठक की। इजरायल कार्यालय ने आईएसए/आईपीईए का कार्य करने में, पेटेंट परीक्षकों के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम व्यवहार के आदान प्रदान के लिए कुछ परीक्षकों को इजरायल भेजने आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की इच्छा प्रकट की।
- (ङ) **ब्रिक्स बैठक:** 2015 की वायपो की सामान्य सभा के साथ-साथ ब्रिक्स बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के कार्यालय प्रधानों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स की चौथी एचआईपीओ, रियो दी जनेरियो, ब्राजील में सहचर बैठक आयोजित की। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भारत ने श्री राजीव अग्रवाल, तात्कालीन महानियंत्रक और संयुक्त सचिव, डीआईपीपी के नेतृत्व में उस बैठक में भागीदारी दी।
- (च) **आईएनपीआई फ्रांस के साथ बैठक:** आईएनपीआई के सीईओ, श्री ईव्स लेपियर और अन्य अधिकारियों ने महानियंत्रक के साथ बैठक की और बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा किए। भौगोलिक उपदर्शन की जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मजबूत बौद्धिक सम्पदा अधिकार वाले दो देशों के बीच सही व्यवसाय कैसे विकसित किया जाये, इस पर चर्चा की तथा विस्तृत नियमों और कार्य योजना के साथ समझौता जापन करने का निर्णय लिया।
- (छ) **डेनमार्क पीटीओ के साथ बैठक:** महानियंत्रक ने जेस्पर कॉग्स्टेड, डायरेक्टर जेनरल और सुश्री एने रिंहोल्ड जर्गसन, डायरेक्टर, नीति और विधायी मामले विभाग, डेनिश पीटीओ के साथ बैठक की। भविष्य में समन्वय सुदृढ़ करने, भौगोलिक उपदर्शन की संरक्षा और प्रोत्साहन तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के कार्य पर चर्चा हुई। डेनमार्क के अधिकारियों ने भारत द्वारा जारी सीआरआई दिशानिर्देशों की भी प्रशंसा की।



- (ज) **ईपीओ के साथ बैठक:** बैठक ईपीओ प्रेसीडेंट श्री बेनोट बेटीस्टेली और महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के साथ अन्य वरीय अधिकारियों के बीच हुई। ईपीओ-भारत कार्ययोजना व परीक्षकों के प्रशिक्षण, 2013 में शुरू की गयी सीपीसी, डाटाबेस का आदान प्रदान विशेषतः ग्लोबल पेटेंट इंडेक्स (जीपीआई) तथा ईपीओक्यूई नेट तथा कार्य योजना के अंतर्गत भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा हुई।
- (झ) **जेपीओ के साथ बैठक:** जेपीओ और आईपीओ के प्रतिनिधिमंडल के बीच 8 अक्टूबर 2015 को बैठक हुई जिसमें श्री हितोषी ईतो, कमीशनर जेपीओ, व जेपीओ के वरीय अधिकारी तथा महानियंत्रक शामिल हुए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन और कार्य योजना पर हस्ताक्षर करने, त्वरित परीक्षण, पेटेंट परीक्षकों की नियुक्ति व 2016 में जापान में सेमिनार आयोजित करने व उसके बाद भारत में सेमिनार आयोजित करने पर चर्चा हुई।
- (ञ) **ओएपीआई के साथ बैठक:** ओएपीआई का प्रतिनिधिमंडल 8 अक्टूबर 2015 को सीजीपीडीटीएम से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों कार्यालयों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन की इच्छा जताई जिसमें सर्वोत्तम व्यवहार का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण तथा ओएपीआई को क्षमता निर्माण में सहायता देने के लिए डाटाबेस के आदान-प्रदान शामिल हो।
5. **वायपो में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन की प्रदर्शनी:** औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग ने 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक वायपो जेनेवो, में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन उत्पादों की एक प्रदर्शनी आयोजित की। इसका उद्घाटन विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के डायरेक्टर जनरल, डॉ फ्रांसिस गुरी और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थाई प्रतिनिधि जिनेवा राजदूत श्री अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। यह भारत सरकार के “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम के तहत “भारत के भौगोलिक उपदर्शन” पर अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी थी। भारतीय कलाकारों ने भी जीआई उत्पादों और अपनी कला का जीवंत प्रदर्शन किया। सामान्य सभा के दौरान सदस्यों को मेक इन इंडिया पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गयी। भारतीय भौगोलिक उपदर्शन की प्रदर्शनी को विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा बहुत सराहना मिली जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में शामिल हुए थे और उन्होंने काफी अभिरुचि दिखाई थी। वायपो के डीजी ने भी सामान्य सभा बैठक के दौरान वायपो में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन का प्रदर्शन करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।





6. भारत और जापान के बीच समझौता जापान और द्विवार्षिक कार्य योजना:

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत और जापान पेटेंट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनोमी, ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री, जापान के बीच 29 जून 2015 को एक समझौता जापान पर श्री अमिताभ कांत, सचिव, डीआईपीपी एवं श्री हितोशी इतो, कमीशनर जेपीओ ने हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य आविष्कारिता को प्रोत्साहित करना और इन कार्यालयों की क्षमता को बढ़ाना था। इसके (समझौता जापान) के अनुसरण में 2015-17 हेतु द्विवार्षिक कार्य योजना पर श्री योशिताके किहारा, डिप्टी कमीशनर जापान पेटेंट कार्यालय और श्री राजीव अग्रवाल, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने दोनों कार्यालयों के बीच सहयोग गतिविधियाँ उल्लिखित करते हुए हस्ताक्षर किए।



7. **ईपीओ भारत सहयोग:** भारत सरकार, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए और कम-से-कम चार वर्षों के लिए ईपीओ और भारत के बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के बीच संरचनाबद्ध कार्य संबंधों के लिए एक कार्य स्वरूप स्थापित किया। इसका प्रारंभिक उद्देश्य सेवा प्रदान करने और दक्षता के संदर्भ में विशेषकर तकनीकी सहयोग के साधनों तथा पेटेंट परीक्षण, प्रशासन और सूचना जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम व्यवहार के आदान-प्रदान द्वारा पेटेंट प्रणाली के विकास में सहायक होना है। इसके तहत, भारतीय पेटेंट कार्यालय, कोलकाता के अधिकारियों ने ईपीओ, वियना, ऑस्ट्रिया में 22 से 24 अप्रैल 2015 तक आयोजित “ईस्ट मिट्स वेस्ट” फोरम में भाग लिया।

8. **वायपो-भारत सहयोग:** औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) ने 13 नवम्बर 2009 को समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य अधिक सक्रिय, प्रणालीबद्ध संगठन और संयुक्त गतिविधियाँ चलाने के माध्यम से भारत सरकार और वायपो के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना था ताकि भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए बौद्धिक सम्पदा के प्रयोग के लक्ष्य को बढ़ावा मिल सके। इसके तहत, समन्वय के लिए प्राथमिकता वाले



क्षेत्र के रूप में पहचान की गई गतिविधियों के लिए बौद्धिक सम्पदा कार्य योजना तैयार की गई है। वायपो और औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने फिक्की के साथ मिलकर 20 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में “मैड्रिड प्रणाली के साथ विदेश में ब्रांड सुरक्षा” पर फेसिलिटेशन कार्यक्रम-सह-सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम-सह-सेमिनार का उद्घाटन श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने किया। मैड्रिड प्रणाली के तहत 1.25 वॉ मिलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न प्राप्त करने पर माइक्रोमैक्स को इस समारोह में वायपो प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।



9. अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बैठक में भागीदारी: पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों (एमआईए) की 22वीं बैठक जापान पेटेंट ऑफिस, टोक्यो, जापान में 4 से 6 फरवरी 2015, के बीच आयोजित की गई। पीसीटी गुणता उपसमूह की अनौपचारिक बैठक भी 2 और 3 फरवरी को आयोजित की गई। इन वार्षिक बैठकों में पेटेंट कार्यालयों के प्रतिनिधि डॉ. के.एस. कर्दम, वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प कर्दम एवं सुश्री रेखा वी. सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने भागीदारी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों की 23वीं बैठक/गुणता उपसमूह का छठा अनौपचारिक सत्र सैंटियागो, चिली में 18 से 19 जनवरी 2016 के बीच आयोजित किया गया जिसमें सुश्री वी. रेखा, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प ने भाग लिया।

10. आईपीओ व जेपीओ के बीच परीक्षक हस्तांतरण कार्यक्रम: दिल्ली के जेटरो नई माध्यम से कार्यालय महानियंत्रक और जापान पेटेंट कार्यालय ने 14 से 16 दिसम्बर 2015 तक पेटेंट कार्यालय नई दिल्ली में आईपीओ और जेपीओ के बीच परीक्षक हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम में भारतीय पेटेंट कार्यालय और जापान पेटेंट कार्यालय के परीक्षकों ने क्रमशः भारतीय पेटेंट प्रणाली और जापानी पेटेंट प्रणाली के बारे में प्रस्तुति दी तथा अपनाए जाने वाले कार्य व्यवहार पर विमर्श किया।





11. फरवरी 2016 में जापान पेटेंट कार्यालय (जेपीओ) में महानियंत्रक का दौरा:

दौरों के कार्यक्रम में महानियंत्रक श्री ओ.पी.गुप्ता द्वारा भारतीय आईपी सेमिनार व जापान में विभिन्न हितधारकों जिसमें इंडो-जापानी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे के साथ बैठक शामिल थी।

- **भारतीय आईपी सेमिनार:** सेमिनार का उद्देश्य भारत सरकार की बौद्धिक सम्पदा के प्रति दृष्टिकोण की स्वयं जानकारी व अद्यतन ब्यौरा एकत्रित करना था व इस सेमिनार में 125 हितधारकों ने भाग लिया। महानियंत्रक द्वारा भारतीय बौद्धिक सम्पदा परिदृश्य के महत्वपूर्ण पहलू दर्शाते हुए विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति दी गयी। प्रतिभागियों ने आईपीओ भारत में हाल के घटनाक्रम व भविष्य के परिदृश्य पर दिये गए विस्तृत विवरण पर संतोष व्यक्त किया।
- **जेपीओ कमीशनर व महानियंत्रक के बीच बैठक:** महानियंत्रक व जेपीओ कमीशनर के बीच दोनों देशों की पेटेंट पद्धति पर परस्पर संवादात्मक चर्चा हुई तथा वैश्विक पेटेंट संबन्धित मुद्दों व दोनों देशों के बीच समन्वय पर भी चर्चा हुई।
- भारतीय परीक्षकों के जापान दौरा जो जेआईपीए द्वारा की जा रही गतिविधियों का हिस्सा है के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जेआईपीए अध्यक्ष मिस्टर तोषिकाजू तनाका के साथ अन्य अधिकारियों और महानियंत्रक के बीच बैठक हुई। महानियंत्रक ने जापान के प्रमुख हितधारक पेनासोनिक व निट्टो डैको का दौरा किया।





अध्याय - X

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि-क्रियाकलाप

परिचय

भारत सरकार ने बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के लिए क्षमता सृजन तथा मानव संसाधन विकास हेतु अपने मिशन को जारी रखा है। इसके लिए पेटेंट तथा व्यापार चिह्न परीक्षकों एवं अन्य अधिशासियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित किए गए हैं।

विगत वर्षों की ही तरह, कार्यालय महानियंत्रक ने आम जनता के साथ-साथ शोध व विकास संस्थानों, वैज्ञानिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालय के लिए संपर्क कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में भी पहल की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों और सरोकारों की विस्तृत समझ बनाने, बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा और प्रवर्तन विषयक ज्ञान प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ व्यवसायों का सशक्तीकरण करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का लाभ उठाना था। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी वायपो, विश्वविद्यालयों, टीआईएफएसी, एनआरडीसी, फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, पीएचडीसीसीआई, एनआईडी आदि जैसे औद्योगिक संगठनों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिशासियों की भागीदारी

वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न के अधिकारियों ने वायपो और विदेशी बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाओं में प्रतिभागिता दी। आईपीओ अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया उनका वर्णन निम्नवत है:





11	27 से 31 जुलाई, 2015 तक जिनेवा में पेटेंट विधान की स्थायी समिति (एससीपी) का 22वाँ सत्र	2
12	24 सितम्बर से 11 दिसम्बर, 2015 तक आयोजित जेपीओ/आईपीआर जारी पेटेंट परीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम	4
13	5 से 14 अक्टूबर, 2015 तक जिनेवा में वायपो के सदस्य देशों का सम्मेलन- बैठक का 55वाँ सत्र	1
14	जिनेवा में 5 से 14 अक्टूबर, 2015 तक पीसीटी यूनियन असेम्बली बैठक	1
15	5 से 10 अक्टूबर, 2015 तक जिनेवा में आयोजित मेक इन इंडिया समारोह	3
16	20 से 22 अक्टूबर तक बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित भौगोलिक उपदर्शन पर विश्व सम्मेलन	1
17	अक्टूबर 26 से नवम्बर 6, 2015 तक बौद्धिक सम्पदा प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग	1
18	20 से 31 अक्टूबर, 2015 तक चुनिंदा मध्य आय देशों (एमआईसी) में स्वास्थ्य तकनीकी पायलट तक प्रवेश बढ़ाने के लिए कंपिटिशन लॉ का उपयोग करते हुए यूएनडीपी द्वारा क्षमता वर्द्धन कार्यशाला	1
19	11 से 13 नवम्बर, 2015 तक वायपो, जिनेवा में आयोजित व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के परिचालन पर राष्ट्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला	2
20	2 से 6 नवम्बर, 2015 तक जिनेवा में आयोजित चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली के विधिक विकास पर वायपो कार्यकारी समूह का 13वाँ सत्र	1
21	9 से 20 नवम्बर, 2015 तक टोक्यो, जापान में आयोजित औद्योगिक सम्पदा परीक्षा- मध्यवर्ती/आधुनिक कार्यक्रम	2
22	23 से 25 नवम्बर, 2015 तक जिनेवा में प्रवर्तन की सलाहकार समिति (एसीई) का 10वाँ सत्र	1
23	25 से 27 नवम्बर, 2015 तक मनीला में पेटेंट एनालिटिक्स हेतु मुक्त और खुला साधन उपकरण पर वायपो अंतर क्षेत्रीय कार्यशाला	





16 कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन किया गया है और लगभग 2000 प्रतिभागियों (विश्वविद्यालय के विद्यार्थी/व्याख्याता तथा अनुसंधान संगठनों के वैज्ञानिक) ने इन कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभागिता दी और उन्हें बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संरक्षा के महत्व से परिचित कराया गया। जिन विश्वविद्यालयों में यह कार्यक्रम संचालित हुए उनकी सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	एन आई टी राउरकेला, उड़ीसा	150
2	वीर सुरेन्द्र साई यांत्रिकी विश्वविद्यालय, संबलपुर, उड़ीसा	140
3	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यूपी	200
4	वनस्थली विश्वविद्यालय, राजस्थान	125
5	जीबी पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन रिसर्च, अलमोड़ा, उत्तराखंड	120
6	देवी अहल्यावाई विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश	75
7	गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब	150
8	पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	120
9	आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, विजाग, आंध्र प्रदेश	200
10	डॉ. बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, श्रीकाकुलम, एपी	100
11	गर्वमेंट महिला कॉलेज, श्रीकाकुलम, एपी	60
12	जेएसएस एकेडमी टेकनिकल एडुकेशन, नोएडा, यूपी	120
13	शिव नाडर विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, यूपी	100
14	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	120
15	मुम्बई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	130
16	जेपी विश्वविद्यालय, नोएडा, यूपी	100





इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय/अनुसंधान संगठन के स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार की अधिकाधिक जागरूकता सृजित करने के प्रयासों को सुदृढ़ बनाना था। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य विशेषकर विद्यार्थी, अनुसंधानकर्ता, व्याख्याता और प्रोफेसर रहे और इनका उद्देश्य इस चरण में जागरूकता सृजित करने के प्रति योगदान करना था।

ख) 2015-16 की अवधि के दौरान, कार्यालय ने भारत और विदेशों में आयोजित वैश्विक प्रदर्शनियों में भाग लिया जिससे भारत में बौद्धिक सम्पदा विशेषकर भौगोलिक उपदर्शन तथा डिजाइन विषयक अभिरुचि सृजित करने में और सहायता हुई। संचालित कार्यक्रमों की सूची निम्नवत है:

I. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सेवाओं का वैश्विक प्रदर्शन- 23 से 25 अप्रैल, 2015:

भौगोलिक उपदर्शन राष्ट्रीय ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन उत्पादों में से कुछ का प्रदर्शन किया। देश के विभिन्न भागों के कलाकारों ने अपनी प्रतिभागिता दी और पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन उत्पादों का प्रदर्शन किया। 40 की संख्या में उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

इस प्रदर्शनी का अनूठा विशिष्ट आकर्षण निजामाबाद के काली मिट्टी के बर्तन, वाराणसी की काष्ठ लाह पात्र कारीगरी, बनारस गुलाबी मीनाकारी, कश्मीर पेपर मैश, वर्ली आर्ट और चेट्टिनाड सूत का जीवंत प्रदर्शन था जहाँ कलाकारों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य आर्कषण माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण व श्री अमिताभ कांत, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग की उपस्थिति रही जिन्होंने कलाकारों से संवाद किया और उनका प्रोत्साहन किया। श्री एन एन प्रसाद, सहायक महानिदेशक (महानिदेशक का कार्यालय) तथा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन ने भी पेलिलियन को देखा। श्री प्रसाद भौगोलिक उपदर्शन की प्रस्तुति से काफी प्रभावित हुए और वायपो की सामान्य सभा के दौरान जिनेवा में पेलिलियन की सहायता करने का प्रस्ताव दिया। श्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव और महानियंत्रक तथा सुश्री पलका साहनी, उपसचिव, डीआईपीपी इस प्रदर्शनी के प्रेरणा स्रोत रहे।

इस स्टॉल में काफी उत्साह देखा गया और थोड़े ही समय में करीब 2000 लोग इसे देखने आए तथा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्राप्त हुई जबकि उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से आर्डर प्राप्त हुए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से लगभग रु. बीस लाख के आर्डर प्राप्त हुए और तीन दिन की वैश्विक प्रदर्शनी के दौरान करीब तीन लाख की बिक्री की गयी।



यह कलाकारों और उनके उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और प्रेरणा रहा।

II. विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस समारोह

- i) **राष्ट्रीय आर पी आर सम्मेलन और राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सम्मान 2015, 24 अप्रैल 2015, प्रगति मैदान, नई दिल्ली**

यह कार्यक्रम सीआईआई, डीआईपीपी तथा महानियंत्रक कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सम्मान, 2015 के अवसर पर श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी और बौद्धिक सम्पदा सम्मान विजेताओं को अपने कर कमलों से सम्मानित किया।

- ii) **मेक इन इंडिया के सर्वप्रमुख साधन के रूप में बौद्धिक सम्पदा सम्मेलन, 29 अप्रैल 2015, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।**
- iii) **फिक्की ने 26 से 28 अप्रैल, 2015 तक ऑन-लाइन स्लोगन और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी संचालित की।**

विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस 2015 के अवसर पर फिक्की ने 15 से 28 अप्रैल तक राष्ट्रीय ऑन-लाइन पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसकी विषय वस्तु विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस 2015 के लिए इस वर्ष की विषय वस्तु -“गेट अप, स्टैंड अप फॉर म्यूजिक” था। यह प्रतियोगिता सभी आयु समूह के लिए थी और इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था-18 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष की आयु से नीचे। प्रतिभागियों को उनकी अर्हता के अनुसार प्रविष्टि भेजने को कहा गया था। इस प्रतिस्पर्धा में कुल 32 प्रविष्टियां विद्यार्थियों, उद्योग, सरकार आदि से प्राप्त हुई जिसमें प्रतिभागिता की सीमा 15 से 63 वर्ष की आयु तक थी।

III. वायपो फिल्म प्रोजेक्ट:

वायपो ने बौद्धिक सम्पदा प्रणाली के प्रयोग से (पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न अथवा कॉपीराइट के प्रयोग द्वारा) लाभान्वित होने वाले सफल आविष्कारक या निर्माता का जीवन चित्रण दिखाने वाली एक फिल्म निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। उस फिल्म का निर्माण सफल रहा है और मेक इन इंडिया के अवसर पर भौगोलिक उपदर्शन की महता दर्शाते हुए इसे प्रदर्शित किया गया।





- IV. मैट्रिड प्रणाली और भारत में इसके प्रयोग के लिए एक मील के पत्थर का उत्सव शीर्षक “1.25वाँ मिलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न का सम्मान और मैट्रिड प्रणाली के साथ विदेश में ब्रांड की संरक्षा पर सेमिनार” सेमिनार जुलाई 20, 2015, फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली।

अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी माइक्रोमैक्स इंफॉमेटिक्स लिमिटेड ने अपने व्यापार चिह्न, माइक्रोमैक्स, के लिए 1.25 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या प्राप्त की। इस रिकार्ड पंजीकरण का उत्सव मनाने और मैट्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डीआईपीपी, फिक्की और वायपो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्न प्रणाली पर एक दिन का समारोह आयोजित किया जिसमें भारतीय व्यवसायी, व्यापार चिह्न समुदाय और सम्बद्ध हितधारक आमंत्रित किए गए।

इस कार्यक्रम में श्री राजीव अग्रवाल (संयुक्त सचिव, डीआईपीपी और महानियंत्रक) तथा श्री एन. एन. प्रसाद, सहायक महानिदेशक और कर्मी प्रधान (महानिदेशक का कार्यालय) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन उपस्थित रहे।

- V. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जिनेवा में भौगोलिक उपदर्शन प्रदर्शनी, 6 से 11 अक्टूबर 2015:

वैश्विक प्रदर्शनी सेवा में भौगोलिक उपदर्शन प्रदर्शनी की सफलता के बाद, 80 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत उत्पादों और देश के विभिन्न भागों के 6 कलाकारों द्वारा सीधी प्रस्तुति की प्रदर्शनी जिनेवा में वायपो साधारण सभा के साथ आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी मेक इन इंडिया पहल का भाग थी और यह बहुत सफल रही।





VI. भौगोलिक उपदर्शन प्रदर्शनी: बौद्धिक सम्पदा और जन अभिरुचि पर वैश्विक कांग्रेस - 15 से 17 दिसम्बर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

चौथे बौद्धिक सम्पदा और जन अभिरुचि पर वैश्विक कांग्रेस में 40 भौगोलिक उपदर्शन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और 4 कलाकारों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस वैश्विक कांग्रेस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल दोनों ने भागीदारी दी और उन्होंने उत्पादों में रुचि दिखाई। कलाकारों को आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया जिससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी।

VII. आईपी विधान एवं आईपीआर के प्रवर्तन पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: "भारत में बौद्धिक सम्पदा की संरक्षा एवं वाणिज्यिकरण- मेक इन इंडिया" 1 से 2 दिसम्बर 2015: होटल इरोस, नई दिल्ली (भारत), साझेदार देश- जापान, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (आईपीओ) ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें विश्व के अन्य बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के प्रतिनिधिमंडल और





हितधारक उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान श्री अमिताभ कांत, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग ने प्रथम सीआईआई औद्योगिक बौद्धिक सम्पदा सम्मान की घोषणा की।

VIII. मेक इन इंडिया सप्ताह में भौगोलिक उपदर्शन- 13 से 18 फरवरी 2015, मुम्बई।

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन और कलाकारों को और प्रोत्साहित करने के लिए 20 उत्पादों की एक प्रदर्शनी डिजाइन स्टॉल पर स्थापित की गई थी। 3 कलाकारों को भी सीधे प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था।

ग) पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम - अगस्त 3, 2015, नई दिल्ली, विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र नगर पुलिस स्टेशन
इस कार्यक्रम में डॉ प्रीतपाल कौर, सहायक पंजीकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, दिल्ली उपस्थित हुई और व्यापार चिह्न विषयक प्रवर्तन उपायों संबंधी प्रक्रियागत जानकारी प्रदान की।

iv) उद्योग द्वारा पेटेंट परीक्षकों के लिए आईसीट फील्ड और एसोचेम द्वारा आईपीओ के साथ मिलकर आयोजित तकनीकी प्रशिक्षण सह कार्यशाला- दिसम्बर 11, 2015

पेटेंट कार्यालय के पेटेंट परीक्षकों और नियंत्रकों के साथ अद्यतन तकनीक पर सूचना साधक करने के उद्देश्य से विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और संबद्ध विषय (आईटी, टेलिकॉम इत्यादि जैसे क्षेत्रों सहित) के क्षेत्र में परीक्षकों के लिए एक कार्यशाला संचालित की गई ताकि उन्हें उद्योग की तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक अनुभव का लाभ प्राप्त हो सके। पेटेंट संबंधी किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई। केवल उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ज्ञान साझा किया गया, इसका उद्देश्य तकनीकी ज्ञान को अद्यतन करना और बढ़ाना था जिसके परिणामस्वरूप गुणता में सुधार होगा, सटीक परीक्षण होगा, प्रक्रिया में उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और पेटेंट का त्वरित निष्पादन होगा।

इसके अतिरिक्त महानियंत्रक कार्यालय के अधिशासियों ने वायपो, विश्वविद्यालयों, टीआईएफसी, एनआरडीसी, फिक्की, सीआईआई, एसोचेम, एनआईडी आदि जैसे अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

ईयू- भारत बौद्धिक सम्पदा समन्वय (आईपीसी-ईयूआई) की एक्टिविटी [यानि भारत और विदेश में ब्रांड बनाने, उनकी संरक्षा और प्रबंधन के लिए बौद्धिक सम्पदा साधनों पर



एसएमई प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना] के अनुपालन के अधीन ईयूआईपीओ ने 4 कार्यशालाएँ नई दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर व मुंबई में आयोजित की।

भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, चेन्नई ने भी वर्ष के दौरान सम्पूर्ण भारत में हितधारकों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है, इसमें किसान, कलाकार और अन्य हितधारक सभी शामिल हैं।

साथ ही एक्टिविटी [यानि विद्यमान और संभावित निर्यात बाजारों में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन की संरक्षा पर भारतीय उत्पादकों और सक्षम प्राधिकारियों को यूरोप में भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण में सहायता देने सहित सुझाव देना] के अनुपालन में ईयूआईपीओ ने 3 भारतीय शहरों में भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण प्रक्रिया (राष्ट्रीय और ईयू) के साथ-साथ विपणन कार्य नीति और निर्यात संभावनाओं के महत्व पर सेमिनार आयोजित किया।





अध्याय - XI

मानव संसाधन

परिचय:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति एवं राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

भारत सरकार ने 11वीं योजना के दौरान अधिक सक्षम सेवा प्रदान करने के लिए "बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण" योजना के तहत 414 पदों की संस्तुति प्रदान की। इनमें 200 पेटेंट परीक्षकों के पद तथा 37 व्यापार चिह्न परीक्षकों के पद शामिल हैं। इसके साथ सरकार ने राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधक संस्थान के लिए 12 अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 12वीं योजना के दौरान "बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण" योजना के तहत सीजीपीडीटीएम कार्यालय में दो वर्ष की अवधि के लिए 481 पदों (पेटेंट कार्यालय के लिए 373 और व्यापार चिह्न के लिए 108) की संस्तुति प्रदान की है। इन पदों के सृजन का अनुमोदन दिनांक 18.03.2015 के पत्र द्वारा सीजीपीडीटीएम कार्यालय को बताया गया है। 12वीं योजना के दौरान सृजित 481 पदों में पेटेंट परीक्षकों के 252 पद और व्यापार चिह्न परीक्षकों के 62 पद शामिल हैं।

इसके अनुसरण में कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के साथ एक सहमति की है जिसके अंतर्गत 459 एकस्व और अभिकल्प के परीक्षकों की नियुक्ति की जा सके जिसमें नवसृजित पदों के साथ-साथ पहले से रिक्त पद शामिल हैं।

1. विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में मानव संसाधन

क. मुम्बई में स्थित कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न:

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न मुख्यालय में निम्नलिखित सहायक कर्मी हैं।



क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	अनुमोदित शक्ति						नियोजित शक्ति													
			कोलकाता		मुम्बई		चेन्नई		दिल्ली		कुल		कोलकाता		मुम्बई		चेन्नई		दिल्ली		कुल	
			गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.	गं. यो.
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	20	11	12	0	10	0	12	1	54	12	19	11	7	0	4	0	12	0	42	11
2	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	क.हिन्दी अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0
4	आशुलिपिक वर्ग-1	समूह ख (अराजपत्रित)	4	0	2	0	2	0	2	0	10	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0
5	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	0	2	0	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	26	12	16	2	14	1	17	2	73	17	22	11	8	0	5	0	14	0	49	11
1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0
2	आशुलिपिक - वर्ग-II	समूह ग	1	0	0	2	0	1	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	25	0	7	9	11	4	14	7	57	20	25	0	2	0	10	3	12	5	49	8
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	0	0	0	5	0	7	0	8	0	20	0	0	0	4	0	0	0	3	0	7
5	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	0	13	0	10	0	12	0	44	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
6	हिन्दी टंकक	समूह ग	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	मल्टी-टास्क स्टाफ	समूह ग	42	0	5	2	10	1	10	4	67	7	31	0	3	2	9	1	5	4	48	7
		कुल	79	0	26	18	32	13	37	21	174	52	57	0	6	6	21	4	19	12	103	22





परिशिष्ट-ग

31 मार्च, 2016 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1.	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	0
2.	सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
3.	वरिष्ठ परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ.उपदर्शन	1	1
4.	आशुलिपिक समूह-II	1	1
5.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	1
	कुल	5	4

परिशिष्ट-घ

31 मार्च, 2016 तक पीआईएस और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	अनुमोदित शक्ति	नियोजित शक्ति
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	1	1
2	कार्यालय अधीक्षक	1	1
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	1
4	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	1
5	आशुलिपिक समूह I	1	1
6	भंडार सहायक	1	1
7	कनिष्ठ प्रलेखन सहायक	1	0
8	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	3	3
9	सहायक अधीक्षक	1	1
10	आशुलिपिक समूह II	1	0
11	शेल्फ सहायक	1	1
12	प्रवर श्रेणी लिपिक	3	3
13	स्वागतकर्ता	1	1
14	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	2
15	अवर श्रेणी लिपिक	3	3
16	हिंदी टंकक	1	1
17	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	6	6
	कुल	29	27